http://amritkalashtimes.com

अमृत कलश टाइम्स

वर्ष : 18
अंक : 128

प्रयागराज गुरुवार 23 जनवरी 2025

पृष्ठः- 4, मूल्यः- एक रूपया

मथुरा के शाही ईदगाह के सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ाई रोक

● अब अप्रैल में होगी सुनवाई

नयी दिल्ली,(एजेंसी)। सीजेआई ने कहा कि शीर्ष अदालत के पास अब तीन मुद्दे लंबित हैं और वे एक इंट्रा–कोर्ट अपील का मुद्दा (हिंदू वादियों द्वारा दायर मुकदमों के एकीकरण के खिलाफ) है, दूसरा पूजा (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 1 अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह में ही अधिनियम है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश पर अपनी रोक बढ़ा दी, जिसमें मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण की अनुमति दी गई थी। भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा कि यह परिसर कृष्ण जन्मभूमि मंदिर के निकट स्थित है, जो हिंदुओं के लिए महत्वपूर्ण धार्मिक महत्व का स्थल है। वह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी वाले सर्वेक्षण के खिलाफश्ट्रस्ट प्रबंधन समिति शाही मस्जिद ईदगाहश्की याचिका पर सुनवाई 1 अप्रैल से शुरू होने वाला सप्ताह तक टाल देगी। सीजेआई ने कहा कि शीर्ष अदालत के पास अब तीन मुद्दे लंबित हैं और वे एक इंट्रा–कोर्ट अपील का मुद्दा (हिंदू वादियों द्वारा दायर मुकदमों के एकीकरण के खिलाफ) है, दूसरा पूजा (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 1 अप्रैल से शुरू होने वाले सप्ताह में ही अधिनियम है। पीठ ने कहा कि इस बीच, शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के अदालत की निगरानी में सर्वेक्षण पर रोक लगाने वाला इलाहाबाद उच्च न्यायालय का अंतरिम आदेश जारी रहेगा।

● यूपी कैबिनेट की बैठक में हुए अहम फैसले ●

विकास को मिलेगी रफ्तार

● महाकुंभ से पांच बड़े एलान, एक्सप्रेसवे और कई ब्रिजों की सौगात
● प्रयागराज–चित्रकूट विकास क्षेत्र के प्रस्ताव को मिली मंजूरी

महाकुंभ नगर,(एजेंसी)। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य राजधानी क्षेत्र (एससीआर) की तर्ज पर प्रयागराज–चित्रकूट विकास क्षेत्र के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में महाकुंभनगर के अरैल क्षेत्र में मंत्रिमंडल की बैठक में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर , रोजगार सृजन और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़े कई अहम प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गयी। मंत्रिमंडल में शामिल भाजपा के सहयोगी अपना दल (एस),निषाद पार्टी और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) भी बैठक में मौजूद रहे। इससे पहले 2019 में यहां आयोजित महाकुंभ के मौके पर योगी मंत्रिमंडल की बैठक हुयी थी। श्री योगी ने बैठक के बाद आयोजित संवाददाता सम्मेलन में महाकुंभ में आये सभी पूज्य संतो और श्रद्धालुओं का स्वागत करते हुये कहा कि यह पहली बार है जब उप्र का संपूर्ण मंत्रिमंडल महाकुंभनगर में उपस्थित है। बैठक में विकास से जुडे नीतिगत मुद्दों और प्रयागराज के विकास से जुड़े मुद्दों पर पर चर्चा हुयी है। उप्र की एयरोस्पेस और डिफेंस और रोजगार से जुडी पालिसी के पांच साल पूरे हो चुके है और इसकी नयी नीति के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की गयी है। उन्होंने घोषणा की कि तीन नए जिलों बागपत, हाथरस और कासगंज में मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे, जिससे स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार होगा और स्थानीय युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार प्रयागराज के सर्वागींण विकास के लिये कटिबद्ध है।

यमुना में भी बनेगा ब्रिज

● साथ ही सिग्नेचर ब्रिज के समानानंतर एक और ब्रिज बनाया जाएगा। सीएम ने कहा कि इन सभी इन्फ्रास्ट्रक्चर का लाभ सभी को मिलेगा। साथ ही इससे प्रयागराज क्षेत्र के विकास को रफ्तार मिलेगी।

प्रशिक्षण कें स्थापित किए जाएंगे

● सीएम ने कहा कि केजीएमयू केंद्र को मेडिकल कॉलेज के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। तीन जिलों हाथरस, कासगंज और बागपत में तीन नए मेडिकल कॉलेज स्थापित किए जाएंगे। 62 आईटीआई, 5 नवाचार, अविष्कार और प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे।

नए प्रोत्साहनों की घोषणा

● सीएम योगी ने कहा विशेष कैबिनेट बैठक के बाद कहा कि पूरी कैबिनेट पहली बार महाकुंभ में मौजूद है। राज्य के विकास से जुड़ी नीतियों पर चर्चा हुई। प्रयागराज से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश एयरोस्पेस और रक्षा तथा रोजगार नीति को पांच साल पूरे हो गए हैं। इसे नवीनीकृत किया जाएगा। अधिक निवेश आकर्षित करने के लिए नए प्रोत्साहनों की घोषणा की गई है।

वकीलों की हड़ताल के कारण राहुल गांधी के मामले की सुनवाई 30 तक टली

नयी दिल्ली,(एजेंसी)। अदालत में पांच साल लंबी प्रक्रिया चली लेकिन राहुल गांधी हाजिर नहीं हुए तो दिसंबर 2023 में तत्कालीन न्यायाधीश ने वारंट जारी कर उन्हें तलब किया था। तब फरवरी 2024 में राहुल गांधी अदालत के समक्ष पेश हुए थे। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष एवं रायबरेली से सांसद राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि मामले की बुधवार को होने वाली सुनवाई अधिवक्ताओं की हड़ताल के कारण पुनः टल गई है। वादी विजय मिश्र के अधिवक्ता संतोष कुमार पांडेय ने बताया कि अधिवक्ताओं की हड़ताल के कारण सांसद–विधायक विशेष अदालत के मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 जनवरी की तारीख निर्धारित की है। कोतवाली देहात के हनुमानगंज निवासी व भाजपा नेता विजय मिश्रा ने 2018 में राहुल गांधी के विरुद्ध मानहानि का मामला एमपी–एमएलए अदालत में दर्ज कराया था। मिश्रा ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि कर्नाटक चुनाव के दौरान राहुल गांधी ने केन्द्रीय मंत्री अमित शाह के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की थी। अदालत में पांच साल लंबी प्रक्रिया चली लेकिन राहुल गांधी हाजिर नहीं हुए तो दिसंबर 2023 में तत्कालीन न्यायाधीश ने वारंट जारी कर उन्हें तलब किया था। तब फरवरी 2024 में राहुल गांधी अदालत के समक्ष पेश हुए थे।

'हार के डर से आपदा वाले घोषणाएं कर रहे'

● भाजपा कार्यकर्ताओं से कहा– वे कहते हैं फिर आएंगे, जनता कहती है फिर खाएंगे

नयी दिल्ली,(एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के जरिए पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये आप–दा वाले अब हर दिन एक नई घोषणा कर रहे हैं। इसका मतलब है कि उनको रोज पराजय की नई–नई खबरें मिल रही हैं। ये इतने डरे हुए हैं कि इन्हें रोज सुबह एक नई घोषणा करनी पड़ रही है। लेकिन अब दिल्ली की जनता इनका खेल समझ गई है। हमने दिल्ली में मुफ्त स्वास्थ्य सेवा के लिए आयुष्मान भारत योजना को लागू करने के लिए श्आप–दाश के लोगों से अनुरोध किया है। लेकिन वे इसे लागू नहीं करना चाहते हैं। मैं दिल्ली के लोगों को बताना चाहता हूं कि इस योजना के कई लाभ हैं। लेकिन आप–दा के लोगों ने इस योजना के कार्यान्वयन में बाधाएं पैदा की हैं।श प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के पार्टी के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, ष्हमने दिल्ली में मुफ्त स्वास्थ्य सेवा के लिए आयुष्मान भारत योजना को लागू करने के लिए श्आप–दाश के लोगों से अनुरोध किया है। लेकिन वे इसे लागू नहीं करना चाहते हैं। मैं दिल्ली के लोगों को बताना चाहता हूं कि इस योजना के कई लाभ हैं। लेकिन आप–दा के लोगों ने इस योजना के कार्यान्वयन में बाधाएं पैदा की हैं।श सीएजी रिपोर्ट के मामले पर अजय माकन ने केजरीवाल को घेरा कांग्रेस नेता अजय माकन ने अरविंद केजरीवाल को सीएजी रिपोर्ट के मामले पर घेरा। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने सीएनजी रिपोर्ट के माध्यम से कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे मगर अब वह 14 रिपोर्ट को विधानसभा सदन के पटल पर नहीं रख रहे हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पार्टी बनाई थी और उसके आधार पर वह सत्ता में आए थे मगर अब अनेक घोटाले हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल विकास कार्य समय पर करने और उनमें पैसे बचाने के फर्जी दावे कर रहे हैं। कांग्रेस ने दावा किया कि 3 अस्पताल के निर्माण में 382 करोड रुपए का घोटाला किया है। केजरीवाल पर हमला बोलते हुए कहा अजय माकन ने कहा कि 2016 से लेकर 2020 तक उन्होंने कई अस्पताल बनाने और बिस्तरों की संख्या बढ़ाने के दावे किए थे मगर अभी तक 1000 बिस्तर बढ़ाई गई है जबकि उन्होंने 32000 बिस्तर की व्यवस्था करने का दावा किया था। अस्पतालों में बिस्तरों की कमी होने के कारण एक–एक बिस्तर पर दो दो तीन तीन मरीज भर्ती किया जा रहे हैं। अस्पतालों में कोई भी सुविधा काम नहीं कर रही है। ऑपरेशन के लिए कई–कई महीने की तिथि दी जाती है।

संग्रहालय की समृद्ध संग्रह और सद्यः संयोजित भागवत प्रदर्शनी कुंभ परंपरा राम कृष्ण को एकात्म करती है- शेखावत

प्रयागराज। इलाहाबाद संग्रहालय में बुधवार को केन्द्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत परिसर स्थित अमर चन्द्रशेखर आजाद प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित किया। तत्पश्चात लघु चित्रों पर आधारित श्भागवतश प्रदर्शनी का शुभारंभ दीप प्रज्ज्वलित किया। उन्होंने कहा कि भारतीय लघु चित्र लोक, परलोक, समाज, कला व संस्कृति का एक साथ प्रतिनिधित्व करते हैं। इस अवसर पर उन्होंने प्रदर्शनी के कैटलॉग का लोकार्पण भी किया। उन्होंने आजाद वीथिका, प्रस्तर मूर्ति कला वीथिका व मृण्मूर्ति वीथिका का अवलोकन किया। निदेशक संग्रहालय राजेश प्रसाद ने संग्रहालय के समृद्ध इतिहास और संग्रहों के महत्ता की जानकारी दी पुनः संग्रहालय के सभा कक्ष में मंत्री ने संग्रहालय के प्रकाशनों त्रैमासिक पत्रिका शविविधाश और संग्रहालय में प्रवेश हेतु विशेष महाकुम्भ टिकट का विमोचन किया।

आज के समय में धर्मग्रंथों का अपमान बढ़ा- पण्डित देवकीनंदन ठाकुर

महाकुंभ नगर। संगम लोअर मार्ग शान्ति सेवा शिविर में बुधवार की कथा में पण्डित देवकीनंदन ठाकुर ने कहा कि मनुष्य को धर्म का पालन करना आवश्यक है। आज के समय में गांव, संत, धर्म, और धर्मग्रंथों का अपमान बढ़ता जा रहा है। यह सनातन धर्म के लिए बहुत बड़ा खतरा है। भगवान और धार्मिक मान्यताओं का अपमान न केवल हमारी संस्कृति, बल्कि हमारे अस्तित्व को भी खतरे में डाल सकता है। उन्होंने कहा कि श्रीमद्भागवत कथा सुनने से मानव जीवन का कल्याण होता है। इसके श्रवण से न केवल वर्तमान जन्म के, बल्कि जन्म–जन्मांतर के पाप भी मिट जाते हैं। यह व्यक्ति को आध्यात्मिक शांति और मुक्ति का मार्ग प्रदान करता है। विश्व में भारत ही एक ऐसा देश है, जहां उसे ष्माँ के रूप में संबोधित किया जाता है। भारतीय संस्कृति और परंपरा में भूमि को देवी के रूप में पूजने की प्रथा अद्वितीय है। यह भावना हमारी सनातन परंपरा और आध्यात्मिकता का आधार है। कुंभ के पवित्र स्नान से जन्म–जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन, और नासिक में आयोजित कुंभ मेले में स्नान करने से आत्मा को शुद्धि और मुक्ति का अनुभव होता है। यह अवसर मानव जीवन में आध्यात्मिक ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार करता है।

मनोहर लाल खट्टर तेलंगाना में विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन

करीमनगर,(एजेंसी)। केंद्रीय शहरी विकास एवं आवास मंत्री मनोहर लाल खट्टर 24 जनवरी को तेलंगाना के करीमनगर जिले का दौरा करेंगे और यहां करीमनगर नगर निगम के तहत कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इस यात्रा के दौरान, श्री खट्टर मंत्री हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में 24 घंटे निरंतर पेयजल आपूर्ति योजना का उद्घाटन करेंगे।

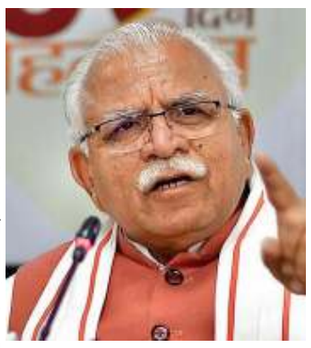

यह परियोजना क्षेत्र के निवासियों के लिए एक बड़ी सुविधा साबित होगी। इसके अलावा, वह अंबेडकर स्टेडियम में नवनिर्मित खेल परिसर और संबंधित सुविधाओं का उद्घाटन करेंगे। इस खेल परिसर का निर्माण 22 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है और यह क्षेत्र के खेल प्रेमियों एवं खिलाड़ियों के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। इन विकासात्मक पहलुओं से शहर की स्थिति में सुधार होगा और नागरिकों को बेहतर सेवाओं का लाभ मिलेगा। वह मल्टीपर्पस स्कूल में 8.2 करोड़ रुपये की लागत से तैयार हुए पार्क विकास परियोजना का उद्घाटन करेंगे, साथ ही राजीव पार्क का नवीनीकरण भी होगा, जिसमें 1.10 करोड़ रुपये का निवेश किया गया है। इसके अलावा, अंबोथू वीर्यम केंद्र में 14 करोड़ रुपये की लागत से एकीकृत बाजार भवन और सुभाष नगर स्कूल तथा मल्टीपर्पस स्कूल में स्मार्ट कक्षाएं स्थापित की गई हैं, जिनकी लागत 10.2 करोड़ रुपये है। ये परियोजनाएं सार्वजनिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए की जा रही हैं। श्री खट्टर करीमनगर बाईपास रोड पर डंप यार्ड का भी दौरा करेंगे, जहां वे इसके प्रभाव के बारे में जनता की शिकायतों का समाधान करेंगे। इसके बाद, वह हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी जाएंगे, जहां वह एक सार्वजनिक बैठक में भाग लेंगे। मंत्री के दौरे से पहले, स्थानीय सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बंडी संजय कुमार, करीमनगर नगर निगम के महापौर सुनील राव और आयुक्त चाहत बाजपेयी ने मंगलवार को विभिन्न परियोजना स्थलों का निरीक्षण किया।

शिक्षा, स्वास्थ्य का बजट बढ़ाए केंद्र सरकार: केजरीवाल

● मिडिल क्लास को आगे बढ़ाने के लिए सड़क से लेकर संसद तक आवाज उठाएंगे

नयी दिल्ली,(एजेंसी)। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मिडिला क्लास टैक्स टेररिज्म का शिकार है। मिडिल क्लास वर्ग सरकारों के लिए सिर्फ एटीएम बन कर रह गया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने जनता के पैसे को जनता पर खर्च किया। दिल्ली में सियासी उठापठक के बीच बुधवार को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मिडिल क्लास परिवारों के लिए अलग से मेनिफेस्टो जारी किया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हर पार्टी ने मध्यम वर्ग को दबाया है। हर चीज पर मध्यम वर्ग को टैक्स देना पड़ता है। अब तो मरने के बाद भी टैक्स देना पड़ता है। 50 फीसदी कमाई टैक्स में जा रही है। मध्यम वर्ग बहुत ज्यादा परेशान है। केजरीवाल ने दावा किया है कि आम आदमी पार्टी ने मिडिल क्लास के लिए बहुत काम किया है। सरकारों के लिए सिर्फ एटीएम है मिडिल क्लासरू केजरीवाल अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मिडिला क्लास टैक्स टेररिज्म का शिकार है। मिडिल क्लास वर्ग सरकारों के लिए सिर्फ एटीएम बन कर रह गया है। आज देश में मिडिल क्लास के लोगों को अपना परिवार चलाने में बहुत मुश्किलें आ रही हैं, इन सभी परेशानियों के कारण ही हर साल लाखों भारतीय देश छोड़कर विदेशों में बस रहे हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार ने जनता के पैसे को जनता पर खर्च किया। हमने जनता के टैक्स के पैसों को शिक्षा और स्कूल पर इन्वेस्ट किया। केजरीवाल ने केंद्र सरकार से कई मांग की हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य का बजट केंद्र सरकार बढ़ाए। श्मिडिल क्लास को आगे बढ़ाने के लिए सड़क से लेकर संसद तक आवाज उठाएंगे। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली के गरीबों और मिडिल क्सास के लोगों को महंगाई की मार से बचाने के लिए आप सरकार ने बिजली–पानी मुफ्त कर दी। हमने शानदार मोहल्ला क्लीनिक और अस्पताल बनाए और मुफ्त इलाज की व्यवस्था की। आने वाले दिनों में हम बुजुर्गों के लिए संजीवनी योजना लेकर आ रहे हैं। यह सब करके क्या हम कोई गुनाह कर रहे हैं?

सम्पादकीय

विश्व राजनीति के लिए महत्वपूर्ण घटनाएं

वैश्विक राजनीति के लिए रविवार और सोमवार के दिन खास महत्वपूर्ण हो गए हैं। एक तरफ रविवार को इजरायल और हमास के बीच युद्धविराम की शुरुआत हो गई है। दोनों पक्षों से एक–दूसरे के बंधकों को छोड़ने का ऐलान हुआ और अब हमास ने इजरायल के कुछ बंधकों को रिहा भी कर दिया है। इधर सोमवार 20 जनवरी को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेकर डोनाल्ड ट्रंप इतिहास में अपनी अलग जगह बना चुके हैं। भारतीय समयानुसार रात साढ़े दस बजे के करीब ट्रंप का शपथग्रहण निर्धारित था। राष्ट्रपति की कुर्सी दोबारा संभालने से पहले वाशिंगटन डीसी में डोनाल्ड ट्रंप अघोषित तरीके से अपना शक्ति प्रदर्शन करते रहे। उनके सम्मान में रात्रिभोज, आतिशबाजी के कार्यक्रम हुए, जिसमें व्यापार, तकनीकी और राजनीति से जुड़ी दिग्गज हस्तियों ने हिस्सा लिया। भारत की तरफ से धनकुबेर मुकेश अंबानी अपनी पत्नी नीता अंबानी के साथ ट्रंप के जश्न में हिस्सा लेने पहुंचे, वहीं ट्रंप के बाएं हाथ बन चुके एलन मस्क भी ट्रंप की शान में कसीदे पढ़ते और अमेरिका को फिर से महान बनाने, बल्कि सदियों तक महान बनाने का संकल्प लेते दिखे। ये नजारे बता रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के इस दूसरे कार्यकाल में अमेरिका में न केवल पूंजीवाद का बोलबाला दिखने वाला है, बल्कि अब भू–राजनैतिक समीकरण भी काफी हद तक बदलेंगे। ट्रंप चार साल सत्ता से बाहर रहने के बाद फिर से व्हाइट हाउस लौट रहे हैं, इससे पहले ग्रोवर क्लीवलैंड के साथ भी ऐसा ही हुआ था, जिन्होंने पहली बार साल 1885 में अमेरिका के राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी, लेकिन 1889 में वे चुनाव हार गए थे और फिर 1893 में उन्होंने दोबारा वापसी की थी। 130 साल बाद अमेरिका फिर ऐसे ही घटनाक्रम का साक्षी बना है।हालांकि चार साल पहले जब डोनाल्ड ट्रंप को डेमोक्रेट जो बाइडेन के सामने हार मिली थी, तब उनके समर्थकों ने जिस तरह कैपिटल हिल पर हमला बोला था, वह दृश्य अमेरिकी लोकतांत्रिक राजनीति के लिए अभूतपूर्व और चौंकाने वाला था। ट्रंप ने तब चुनावों में धोखाधड़ी का इल्जाम लगाया था, वे बाद में कई मौकों पर पीड़ित की तरह प्रस्तुत करते रहे और सत्ता में लौटने का ऐलान उनकी तरफ से होता रहा। पिछले साल राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान जुलाई में जब उन पर गोली चली और वे बाल–बाल बचे, तब इस बात की प्रबल संभावनाएं बन गईं कि अब ट्रंप सत्ता में वापसी करेंगे। इस संभावना को जो बाइडेन की गिरती साख ने और बल दिया। डेमोक्रेटिक पार्टी के भीतर ही बाइडेन की उम्मीदवारी पर दो फाड़ हो गए। इजरायल–फिलीस्तीन युद्ध और रूस–युक्रेन युद्ध में अमेरिका की भूमिका को लेकर बाइडेन से नाराजगी जाहिर होने लगी। चुनाव अभियान के बीच में ही बाइडेन की जगह उनकी उपराष्ट्रपति रहीं कमला हैरिस को डेमोक्रेटिक पार्टी ने अपना उम्मीदवार बना दिया। इन सबमें रिपब्लिकन पार्टी और डोनाल्ड ट्रंप को फायदा हुआ और उन्होंने फिर से जीत दर्ज की। एलन मस्क और मार्क जुकरबर्ग जैसे लोगों का ट्रंप के साथ खड़ा होना भी जो बाइडेन की हार का कारण बना। अपनी ऐतिहासिक जीत को यादगार बनाने के लिए ट्रंप ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उनके शपथग्रहण के लिए मेहमानों की सूची से लेकर उनकी घोषणाएं सब पर चर्चा हो रही है। ट्रंप को फिर से राष्ट्रपति बनते देखने के साक्षी लोगों में एलन मस्क, मार्क जुकरबर्ग, जेफ बेजोस, सुंदर पिचाई, टिम कुक जैसे तकनीकी शक्ति से लैस धन कुबेरों के अलावा अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जेवीयर मिली, इटली की प्रधानमंत्री जियार्जिया मेलोनी, जर्मनी के अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी (एएफडी) पार्टी के टीनो श्रुपाला और ब्रिटेन की पॉपुलिस्ट पार्टी–श्रिफॉर्म पाटीश के नेता नाइजल फराज का नाम भी शामिल है। ये सूची बताती है कि दक्षिणपंथ और पूंजीवाद को ट्रंप ने खुल कर बिना किसी झिझक के तरजीह दी है। अपने विदाई भाषण में जो बाइडन ने जैसी चेतावनी दी थी कि अमेरिका चंद टेक अरबपतियों के दबदबे वाली ओलिगार्की (अल्पतंत्र) में तब्दील हो सकता है, तो वह चेतावनी ट्रंप के नए कार्यकाल की शुरुआत के साथ ही सच होती दिख रही है। उद्योगपति चुनावों में मदद करते हैं और सत्ताधारियों को दबाव में लेकर अपने मतलब की नीतियां बनवाते हैं, यह तो खुला सच है ही, लेकिन जिस तरह से एलन मस्क ट्रंप के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं, वह लोकतांत्रिक राजनीति में एक नए किस्म का चलन शुरु कर रहा है। हो सकता है आगामी वक्त में भारत में भी ऐसे नजारे देखने मिलें। वैसे ट्रंप के आमंत्रितों में नरेन्द्र मोदी का नाम शामिल न होने पर भी काफी सवाल उठे। माना जा रहा है कि पिछले सितम्बर में अपनी अमेरिका यात्रा में नरेन्द्र मोदी ने ट्रंप से मुलाकात में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई, इस वजह से ट्रंप ने कोई गांठ बांध ा ली है। हालांकि परस्पर लाभ और लेन–देन के संबंधों में ऐसी गांठें नहीं बनाई जातीं। लेकिन हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप जैसे आयोजनों के बाद नरेन्द्र मोदी को ट्रंप के शपथग्रहण में न बुलाना और वहीं शी जिनपिंग को ट्रंप द्वारा खुद निमंत्रित करना वैश्विक संबंधों में नए समीकरण की तरफ इशारा करता है। शी जिनपिंग इस समारोह में नहीं गए, उनकी जगह उप राष्ट्रपति हान झेंग पहुंचे हैं, वहीं भारत से विदेश मंत्री एस.जयशंकर इस समारोह के लिए पहुंचे हैं। बहरहाल, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने नए कार्यकाल की शुरुआत से पहले बड़ा दावा किया कि वे तीसरा विश्वयुद्ध रोक देंगे। यूक्रेन में युद्धविराम कराएंगे और साथ ही अमेरिका में अवैध ा अप्रवासियों को बाहर करने के लिए आक्रामक अभियान चलाएंगे। अपने देश की सीमाओं के भीतर ट्रंप क्या फैसले लेते हैं, यह उनका अधिकार है। लेकिन विश्वयुद्ध की आशंकाओं को रोकने का दावा वाकई बड़ा है। क्योंकि अब तक अमेरिका की शह पर ही इजरायल और यूक्रेन युद्ध क्षेत्र में बने हुए हैं, यह खुला सच है। फिलीस्तीन पर पिछले 15 महीनों से चल रहे इस युद्ध में लाखों बेकसूर मारे गए और गजा तो पूरी तरह से बर्बाद ही हो गया। हमास के खात्मे के नाम पर इजरायल ने जो क्रूरता दिखाई, उसे नरसंहार के अलावा और कुछ नहीं कहा जा सकता। निर्दोष नागरिकों, पत्रकारों, मदद करने वाले संगठन, डाक्टर, नर्सें, शांति कार्यकर्ता सब इस युद्ध की चपेट में आए। अंतरराष्ट्रीय बिरादरी इजरायल पर कोई अंकुश नहीं लगा पाई, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता संभालते ही शांति के आसार बनना अच्छी बात है। मगर इस शांति की आड़ में पूंजीवाद कोई और भयानक खेल न शुरु कर दे, इस बारे में वैश्विक बिरादरी को सचेत रहना होगा।

भारत के लोकतंत्र की परीक्षा लेने वाला ममता का बयान, आखिर कहना क्या चाहती हैं दीदी

❍ राजनीतिक स्वार्थ साधने के लिए एक राज्य की मुख्यमंत्री अगर बीएसएफ पर ही घुसपैठ के आरोप लगाए, तो इससे बुरी बात क्या हो सकती है।

बिमल राय

आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत के 'असली स्वतंत्रता' वाले बयान को ममता बनर्जी ने देशद्रोह कहा है, लेकिन सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) पर घुसपैठ का आरोप लगाकर क्या वह राष्ट्रविरोधी बयान नहीं दे रही हैं? पश्चिम बंगाल जैसे सूबे की मुख्यमंत्री अगर कहें कि बीएसएफ राज्य में घुसपैठ करवा रहा है, तो इसे हल्के में नहीं ले सकते। यह कथन भारत के लोकतंत्र की परीक्षा लेने वाला है। हालांकि बंगाल में चुनावी हिंसा और पक्षपाती शासन की वजह से स्थितियां पहले से ही नाजुक हैं। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का हालिया बयान हमारे बहादुर सैनिकों का अपमान है। बंगाल की सीमा भी ऐसे देश से लगी है, जो अब भारत को अपना दुश्मन मानने का दुस्साहस कर रहा है। पहले तो वहां भारतीय सामानों के बहिष्कार की हवा बनाई गई और फिर तख्तापलट हो गया। जेल से हजारों आतंकियों की रिहाई के बाद हिंदुओं पर अत्याचार शुरू हुआ। अब शेख हसीना के प्रत्यर्पण के लिए पत्राचार और पाकिस्तान से बढ़ती दोस्ती ने ढाका के इरादे साफ कर दिए हैं। इन हालात में चाहिए था कि मुख्यमंत्री ममता असम और त्रिपुरा सरकारों की तरह सीमा पर बीएसएफ की मदद में स्थानीय पुलिस और प्रशासन को भी झोंकतीं, लेकिन दुर्भाग्य से वह उल्टे बीएसएफ पर आरोप लगा रही हैं। बांग्लादेश से लगी बंगाल की सीमा 2,216 किलोमीटर लंबी है, जिसमें से करीब 20 फीसदी हिस्से में बाड़ नहीं है। कई जगह नदियों को बॉर्डर माना गया है। इस लेखक ने स्वयं उत्तर 24 परगना के हाकिमपुर बॉर्डर का दौरा किया था और देखा था कि गर्मी के दिनों में उस नदी को पैदल ही पार किया जा सकता है। बीएसएफ की चौकसी के

बावजूद रात में घुसपैठ के अलावा ड्रग, सोना, चीनी, प्याज जैसे खाद्य पदार्थों और नकली भारतीय मुद्रा की तस्करी होती है। आरोप लगाने से पहले ममता को यह बताना चाहिए था कि कम से कम 72 स्थानों पर बीएसएफ की चौकियां बनाने के लिए जमीन देने में सरकार क्यों विफल है? सीमावर्ती गांवों के लोगों से अदालतों में फर्जी दीवानी मुकदमे क्यों करवा दिए जाते हैं? इसके अलावा भी पुलिस की भूमिका संदिग्ध होती है। घुसपैठियों को पकड़कर बीएसएफ स्थानीय पुलिस को सौंप देती है। उन्हें अदालत में पेश किया जाता है और ज्यादातर मामलों में पुलिस जमानत का विरोध ा नहीं करती है। जमानत पाकर वे स्थानीय नेताओं और दलालों की शरण में जाते हैं, जो उन्हें आधार, वोटर कार्ड आदि बनवाने की व्यवस्था करते हैं। इस तरह हर साल हजारों बांग्लादेशी भारतीय नागरिक बना दिए जाते हैं।

सवाल है कि सीमा को असुरक्षित रखने के पीछे के राजनीतिक स्वार्थ और बीएसएफ के खिलाफ जघन्य आरोप लगाकर कोई कानून के दायरे से बाहर कैसे रह सकता है? आलो रानी सरकार नामक बांग्लादेशी महिला तृणमूल के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ती है। रशीदाबाद ग्राम पंचायत की मुखिया लवली खातून भी बांग्लादेशी है, जो तृणमूल में शामिल होकर पंचायत चुनाव जीती है। ऐसे सैकड़ों मामले हो सकते हैं। पिछले साल 28 दिसंबर को बांग्लादेशियों के लिए अवैध रूप से पासपोर्ट बनवाने के खेल का खुलासा हुआ, जब उत्तर 24 परगना के गायघाटा में मास्टरमाइंड मनोज गुप्ता की गिरफ्तारी हुई। रैकेट में शामिल एक पूर्व पुलिसकर्मी अब्दुल हई तीन जनवरी को इसी जिले के कमरपुर से गिरफ्तार हुआ। उसके बैंक खाते से अवैध कमाई के 12.5 लाख रुपये बरामद हुए। यह गिरोह आधार कार्ड के लिए 15 हजार, वोटर आईडी कार्ड के लिए 10 हजार, जन्म प्रमाणपत्र के लिए 12 हजार और पैन कार्ड के लिए 3,000 रुपये वसूल रहा था। पूरे घोटाले के संबंध ा में उत्तर 24 परगना के बारासात कोर्ट के लॉ क्लर्क समीर दास सहित कुल नौ लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस ने माना है कि ट्रैवल एजेंसी की आड़ में संचालित यह रैकेट घुसपैठियों, खासकर बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध रूप से 73 फर्जी भारतीय पासपोर्ट जारी करवा चुका है। सवाल है कि बिना उचित सत्यापन किए ये पासपोर्ट कैसे जारी हो गए? बांग्लादेश में तख्तापलट के बाद जेल से छूटे आतंकी भारत में घुसने की फिराक में हैं। बंगाल के विशेष कार्य बल और असम पुलिस ने 18 और 30 दिसंबर को मुर्शिदाबाद से प्रतिबंधित अंसारुल्लाह बांग्ला टीम (एबीटी) के चार आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। पहले असम में जेएमबी के तीन आतंकी पकड़े गए थे, जिनसे पूछताछ के बाद मुर्शिदाबाद में स्लीपर सेल के रूप में काम करने वाले आतंकियों के ठिकाने का पता चला। 18 जनवरी को मालदा जिले के वैष्णवनगर सीमा के पास बाड़ लगा रहे बीएसएफ जवानों व स्थानीय लोगों पर दो बम फेंकेघ्गए, जिसमें दो जवान घायल हो गए। त्रिपुरा सीमा पर भी बांग्लादेशी उपद्रवियों ने एक बीएसएफ जवान से बंदूक छीनने की कोशिश की। 18 जनवरी को ही बांग्लादेश सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस ने सेना को जंग के लिए तैयार रहने के लिए कहा।

आरजी कर कांड में अदालती फैसले के बाद भी नहीं मिल पाए कई सवालों के जवाब

❍ पीड़िता के माता-पिता के अलावा इस घटना के विरोध में महीनों से आंदोलन करने वाले जूनियर डश्वक्टरों और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तक ने अभियुक्त को फांसी की सजा नहीं मिलने पर असंतोष जताया है।

प्रभाकर मणि तिवारी

कोलकाता के आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर के साथ रेप के बाद उसकी हत्या के मामले में कोलकाता की एक अदालत ने इस मामले के इकलौते अभियुक्त संजय राय को आजीवन कारावास की सजा तो सुना दी है। लेकिन इस घटना से संबंधित कई सवालों के जवाब अब भी अधर में हैं। दूसरी ओर अभियुक्त के वकील ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। सीबीआई की दलीलों के बावजूद जज ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला नहीं माना। दूसरी ओर, पीड़िता के माता–पिता के अलावा इस घटना के विरोध में महीनों से आंदोलन करने वाले जूनियर डॉक्टरों और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तक ने अभियुक्त को फांसी की सजा नहीं मिलने पर असंतोष जताया है। पीड़िता के पिता का कहना था कि सीबीआई इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामला साबित करने में नाकाम रही है। अगर वैसा होता तो अभियुक्त को फांसी की सजा मिलती। उनका कहना था कि इस मामले में अभी कई अन्य लोग भी शामिल हैं। उन सबको कटघरे में लाना चाहिए। हमारी लड़ाई जारी रहेगी। जूनियर डॉक्टरों के संगठन वेस्ट बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट ने भी यही बात कही है। उधर, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि हमने दोषी के लिए फांसी की मांग उठाई थी। अगर यह मामला कोलकाता पुलिस के हाथों में होता तो दोषी को फांसी की सजा ही मिलती। बीते साल नौ अगस्त को आर.जी. कर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर का शव बरामद किया गया था। उसके साथ रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। पुलिस ने सीसीटीवी के फुटेज और दूसरे सबूतों के आधार पर इस मामले में कोलकाता के पुलिस के सिविक वालंटियर संजय को गिरफ्तार किया था। 13 अगस्त को कलकत्ता हाईकोर्ट ने इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी थी। इस घटना ने लंबे समय तक देश–विदेश में सुर्खियां बटोरी थी। दूसरी ओर, इस घटना के विरोध में राज्य के तमाम जूनियर डॉक्टरों ने लंबे समय तक धरना–प्रदर्शन और आमरण अनशन किया था। अदालत में पीड़िता के माता–पिता के अलावा सीबीआई ने इसे श्रेयरेस्ट ऑफ द रेयरश मामला बताते हुए अभियुक्त के लिए मौत की सजा की मांग की थी। लेकिन बचाव पक्ष के वकील ने अदालत से संजय को सुधरने का एक मौका देने की अपील करते हुए कहा था कि उसको मौत की सजा नहीं दी जाए। इस मामले की सुनवाई बीते 11 नवंबर को शुरू हुई थी। यानी नौ महीने बाद फैसला आया है, लेकिन अब भी इससे जुड़े कई सवालों के जवाब अंधेरे में हैं। वेस्ट बंगाल

डॉक्टर्स फ्रंट से जुड़े डॉ. किंजल नंद बताते हैं कि शुरू से ही इस मामले की जांच में भारी लापरवाही बरती गई और कई अहम सबूतों को या नष्ट होने दिया गया या फिर उसे नष्ट करने वालों से ठीक से पूछताछ नहीं की गई। उनका सवाल था कि पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और स्थानीय थाने के ऑफिसर इंचार्ज अभिजीत मंडल को सबूत मिटाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। लेकिन सीबीआई तय समय सीमा में उनके खिलाफ आरोपपत्र दायर नहीं कर सकी। नतीजतन उनको जमानत मिल गई। आखिर सीबीआई ने ऐसा क्यों किया? उनका सवाल है कि पीड़िता का शव सुबह बरामद होने के बाद उसका पोस्टमार्टम शाम को किया गया और प्राथमिकी रात को पौने 12 बजे दर्ज की गई थी। इसमें पहले अस्वाभाविक मौत का मामला दर्ज किया गया था जबकि शव की स्थिति ही अपनी कहानी बता रही थी। आखिर इतनी देरी क्यों हुई और अस्वाभाविक मौत का मामला क्यों दर्ज किया गया था? उनका सवाल है कि अस्पताल से पीड़िता के घर फोन पर यह क्यों बताया गया था कि आपकी बेटी बीमार है और उसने शायद आत्महत्या कर ली है? अब तक यह पता नहीं चल सका है कि किसने और किसके कहने पर वह फोन किया था। डॉ. किंजल सवाल करते हैं कि घटना के अगले दिन ही मौके पर एक कमरे की दीवार क्या सबूत मिटाने के लिए तोड़ी गई थी? 14 अगस्त की आधी रात के समय जुलूस की शक्ल में आने वाले लोगों ने क्या मौके से सबूत मिटाने के लिए ही अस्पताल पर हमला किया था? वहां सुरक्षा का पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं किया गया था? जूनियर डॉक्टरों का कहना है कि इन सवालों का जवाब नहीं मिलने तक पूरी तस्वीर साफ नहीं होगी।

ट्रम्प शासन के शुरुआती दौर में भारतीय रुपये में गिरावट का खतरा वास्तविक

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपये की विनिमय दर में हाल ही में हुई अस्थिरता ने इस बात पर बहस को जन्म दिया है कि केंद्रीय बैंक को राष्ट्रीय मुद्रा के प्रगतिशील अवमूल्यन की स्थिति पर कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। कुछ टिप्पणीकारों और रिपोर्टों के अनुसार, रुपया कुछ ही समय में 90 डॉलर के स्तर पर पहुंच सकता है। भारत के अग्रणी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक ने रुपये–डॉलर की दरों में मौजूदा उतार–चढ़ाव को श्ट्रम्प टैंट्रम्सश के रूप में वर्णित किया है, जो कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व के अपने शानदार अध्यक्ष, बेनबर्नानके के तहत नीति सुधार चरण के दौरान पहले जो हुआ था, उसके संदर्भ में है। बर्नानके प्रभावशाली अर्थशास्त्रियों में से एक थे और 1930 के दशक की महामंदी पर उनके काम ने उन्हें 2008 के वैश्विक वित्तीय मंदी के बाद की स्थिति को संभालने के लिए एक विशेष उपकरण प्रदान किया। ऐसी स्थिति का सामना करते हुए जिसमें केंद्रीय बैंकर अर्थव्यवस्था के व्यवहार को प्रभावित करने के लिए ब्याज दर भिन्नता जैसे मौद्रिक नीति साधनों का उपयोग करने में असमर्थ थे, प्रमुख केंद्रीय बैंकरों ने श्मात्रात्मक सहजताश (क्यूई) के रूप में जाना जाने वाला उपाय शुरू किया था। इसमें वित्तीय परिसंपत्तियों की खरीद करके सिस्टम में अधिक तरलता जारी करना और इस प्रकार नये फंड डालना शामिल था। स्थिति स्थिर होने के बाद, क्यूई जारी रहा और फिर वह समय आया जब इन्हें रोकना पड़ा–अर्थात्नीति उलटने का जमाना आया। बर्नानके ने अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से इस प्रक्रिया की शुरुआत की थी, जिसके कारण 2012–13 में वैश्विक वित्तीय उथल–पुथल मच गयी थी। तब जो हुआ था, वह यह था कि नीतिगत रुख के उलट होने से उभरते बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) से धन का पलायन हुआ और वापस अमेरिका में आ गया। परिणामस्वरूप, ईएमई की मुद्राओं में एक तरह की गिरावट आई और विनिमय स्थिरता ने ईएमई को गंभीर रूप से प्रभावित किया। सबसे अधिक प्रभावित लोगों को एक नाम भी दिया गया था, फ्रैंजाइल फाइव। वित्त विशेषज्ञों के बीच उस चरण को टेपरटैंट्रम के रूप में जाना जाता था, क्योंकि अमेरिकी फेडरल रिजर्व प्रणाली द्वारा बॉन्ड खरीद को कम किया गया था। नये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा आर्थिक कार्रवाइयों की एक श्रृंखला का सुझाव देने के साथ, वित्तीय बाजारों द्वारा एक समान अस्थिरता प्रकट की जा रही है। यह स्पष्ट और स्पष्ट रूप से घबराहट है। डोनाल्ड ट्रम्प उन देशों पर टैरिफ लगाने की धमकी दे रहे हैं, जिनके निर्यात बाजार अमेरिका में हैं। इस प्रकार, ट्रम्प कह रहे हैं कि वे केनडा, मैक्सिको और सबसे बढ़कर, चीन पर उनके उत्पादों पर टैरिफ लगायेंगे जो अमेरिकी बाजार में प्रवेश करते हैं। ट्रम्प ने भारत को भी नहीं बख्शा है। उन्होंने अक्सर भारत को टैरिफ किंग के रूप में वर्णित किया है, यह इंगित करते हुए कि भारत अक्सर संयुक्त राज्य अमेरिका से आयात पर टैरिफ लगाता है।ट्रम्प टैरिफ का उद्देश्य बाहर से आयात को सीमित करना है। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक रूढ़िवादी निरंकुश शासन स्पष्ट रूप से आयात को प्रतिबंधित करेगा और इसके बजाय अमेरिकी मांगों को बाहर से आयात करने के बजाय घरेलू उत्पादित वस्तुओं पर निर्देशित करेगा। उम्मीद है कि इससे ट्रम्प के समर्थकों और उनके अनुयायियों द्वारा घोषित और प्राप्त की गयी तथाकथित मेक अमेरिका ग्रेट अगेन (मगा)कार्य योजना – अमेरिका को फिर से महान बनाओ– को बहाल या हासिल किया जा सकेगा। हालांकि, अमेरिका और उसके व्यापार भागीदारों में जमीनी स्तर की आर्थिक स्थिति को देखते हुए, आयात को प्रतिबंधित करने वाले टैरिफ अमेरिका के अंदर आपूर्ति दबाव पैदा करेंगे। जैसा कि अर्थशास्त्र के जाने–माने प्रोफेसरों में से एक बैरी आइचेन ग्रीन ने तर्क दिया है, संयुक्त राज्य अमेरिका के भीतर विनिर्माण की कठोरता के कारण, अमेरिकी उपभोक्ताओं को घरेलू कमी को दूर करने के लिए आयातित वस्तुओं की ओर रुख करना होगा। ऐसा होने के लिए, विदेशी उत्पादों को खरीदना अभी भी सस्ता बनाने के लिए अमेरिकी डॉलर को मजबूत करना होगा। इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि अल्पावधि में, अमेरिकी डॉलर में वृद्धि के लिए भारी दबाव आयेगा। व्यापारिक साझेदारों को अपनी अर्थव्यवस्थाओं को स्थिर करने में अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। पहले से ही, कई प्रतिस्पर्धी मुद्राएं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चीनी मुद्रा ने डॉलर के मुकाबले निचले स्तर दिखाये हैं। ट्रम्प के राष्ट्रपति बनने के साथ अमेरिका की नयी वास्तविकताओं के लिए इस तरह के वैश्विक समायोजन की स्थिति में, भारतीय वित्तीय क्षेत्र को नई वास्तविकताओं के मद्देनजर समायोजित करने के लिए बहुत सतर्क दृष्टिकोण अपनाना समझदारी होगी। नयी वास्तविकताएं और रुझान क्या हैं जिनके खिलाफ भारतीय केंद्रीय बैंक को निकट भविष्य के लिए अपनी नीतियां बनानी चाहिए? सबसे पहले, बाजार की ताकतों के खिलाफ मुद्रा की विनिमय दर को वास्तव में नियंत्रित करना लगभग असंभव है। क्या होता है जब केंद्रीय बैंक दरों को स्थिर करने के लिए बाजार में हस्तक्षेप करने के लिए भारी मात्रा में धन खर्च करते हैं। हस्तक्षेप समाप्त होने के तुरंत बाद मुद्राओं पर हमले फिर से शुरू हो जाते हैं। ऐसा बार–बार हुआ है। दूसरे, मुद्रा दरें आम तौर पर एक अवधि में घरेलू ताकत और कमजोरियों को दर्शाती हैं। इस प्रकार, समग्र व्यापार में रुझान, घरेलू मूल्य स्तर, ब्याज दरें और इसी तरह के कारक दीर्घकालिक संभावनाओं को प्रभावित करते हैं। जहां तक भारतीय विदेशी मुद्रा बाजार का सवाल है, दरें लगभग सीधे तौर पर व्यवहार से जुड़ी हुई हैं। विदेशी संस्थागत निवेशकों के लिए यह एक बड़ी चुनौती है। अगर विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) घरेलू बाजार में बिकवाली करते हैं और फिर अपने फंड निकाल लेते हैं, तो रुपया दबाव में आ जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक बुलेटिन के ताजा अंक में प्रकाशित एक पेपर में इस बारे में लिखा है। यह प्रवृत्ति कोई नई नहीं है। यह 2008 के बाद की वित्तीय मंदी के दौर में देखी गयी थी। इस तरह की पृष्ठभूमि में बाजार को स्थिर करने के लिए आरबीआई का भारी हस्तक्षेप कुछ हद तक निरर्थक है। बेशक, ये हस्तक्षेप अपने तात्कालिक लक्ष्य को हासिल करते हैं–अर्थात तत्काल दरों को स्थिर करते हैं। लेकिन विदेशी मुद्रा बाजार का एक और पहलू है – सख्त तकनीकी कारक जो अक्सर बढ़ जाते हैं और उन्हें थोड़ा ठीक करने की जरूरत होती है। ऐसा ही एक कारक विदेशी गैर–वितरणीय रुपया व्यापार प्रवृत्ति है। ये पूरी तरह से सट्टा हैं और वास्तव में डिलीवर करने योग्य नहीं हैं। जब रघुराम राजन ने रिजर्व बैंक के गवर्नर का पद संभाला था, तब इसने कुछ हद तक महत्व हासिल कर लिया था। एक अच्छे अर्थशास्त्री होने के नाते, उन्होंने विदेशी गैर–वितरणीय बाजार को नियंत्रित करने के लिए बहुत सफलतापूर्वक कदम उठाये थे। उन दिनों के सबक पर फिर से विचार करना उचित हो सकता है और उनमें से कुछ सबक शिक्षाप्रद हो सकते हैं। हालांकि, रुपये की विनिमय दर में उतार–चढ़ाव को रोकने के लिए हस्तक्षेप के लिए एक विस्तृत और निरंतर कार्यक्रम प्रति–उत्पादक हो सकता है और हम विदेशी मुद्रा भंडार का एक अच्छा हिस्सा बर्बाद कर सकते हैं। ट्रंप शासन अमेरिका को प्राथमिकता देने की अपनी योजनाओं के साथ वैश्विक अर्थव्यवस्था को अशांत करने की क्षमता रखता है। निश्चित रूप से अस्थिर वित्तीय बाजार और सीमाओं के पार पूंजी का बड़ा प्रवाह होगा, जो कई अन्य मापदंडों को अज्ञात क्षेत्रों में छोड़ देगा, विनिमय दरों को तो छोड़ ही दें। हमें अपनी चौकसी कम नहीं करनी चाहिए। किसी भी दर पर, रिजर्व बैंक के पास उथल–पुथल के समय विनिमय बाजार को संभालने की बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी संस्थागत स्मृति है। आरबीआई जानता है कि ऐसी स्थिति में कैसे आगे बढ़ना है।

11 लाख लीटर दूध का उत्पादन और खपत 22 लाख लीटर की, काशी में बढ़ा सिंथेटिक दूध का कारोबार

वाराणसी। काशी में रोजाना दूध का उत्पादन करीब 11 लाख लीटर है, जबकि खपत 22 लाख लीटर से अधिक यानी दोगुने से भी ज्यादा है। दुग्ध उत्पादक संघ के मुताबिक इससे सिंथेटिक दूध और दुग्ध उत्पादों का बाजार चल निकला है। यह लोगों की सेहत के साथ जेब पर असर डाल रहा है। वहीं, मिलावट खोरों पर प्रशासन अंकुश नहीं लगा पा रहा है। दरअसल, दुग्ध बाजार में सिर्फ वाराणसी ही नहीं चुनार–मिर्जापुर, चंदौली, गाजीपुर से भी दूध आता है। दूध से खोआ, छेना, पनीर, दही, लस्सी मठ्ठा आदि भी तैयार किए जाते हैं। तरह–तरह की मिठाइयां बनती हैं। पनीर भी घरों के साथ–साथ वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों को बेचा जाता है। शादी–समारोहों के अलावा विभिन्न आयोजनों में पनीर के तरह–तरह के व्यंजन बनाने का फैशन चल निकला है। चाय की दुकानों पर दूध की खपत जबरदस्त होती है।

5,82, 120 पशु, इसमें 50 फीसदी दुधारू

वाराणसी मंडल के उप दुग्ध शाला अधिकारी अखिलेंद्र मिश्र ने बताया कि जिले में गाय की संख्या 3,25,679 और 2,56,441 मवेशी (भैंस) सहित 5,82, 120 पशु हैं। इसमें 50 प्रतिशत दुधारू हैं। प्रति पशु चार लीटर के हिसाब से करीब 11,64,240 लीटर दूध का उत्पादन है। इसके अलावा चंदौली, जौनपुर, मिर्जापुर, सोनभद्र आदि जनपदों से रोजाना दो लाख लीटर दूध, पराग डेयरी से 25 हजार लीटर और अमूल डेयरी से 75 हजार लीटर दूध की आपूर्ति होती है। फिर भी वर्तमान में सात से आठ लाख लीटर दूध की कमी है। बाजार सूत्रों की मानें तो इस कमी की भरपाई के लिए सिंथेटिक व मिलावटी दूध का उपयोग किया जा रहा है।

प्रति व्यक्ति 3.50 एमएल दूध की जरूरत

अर्थ संख्या अधिकारी संजीव कुमार बघेल ने बताया कि वाराणसी की वर्तमान आबादी 46 लाख से अधिक है।

ईवीएम वेयरहाउस का निरीक्षण कर रखरखाव की जानकारी ली

मऊ। जिला अधिकारी प्रवीण मिश्र ने मंगलवार को ईवीएम वीवीपैट वेयरहाउस का राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में निरीक्षण किया। इस दौरान जिलाधिकारी ने वेयरहाउस के चारों तरफ लगाए गए सीसीटीवी कैमरों की सक्रियता, कंट्रोल रूम, कक्षवार विद्युत आपूर्ति, खिड़कियों और रोशनदानों को सुरक्षित रखने की जानकारी ली। उन्होंने वेयरहाउस के बाहर लगाए गए सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से वाह्य सुरक्षा व्यवस्था की अनवरत निगरानी करने के निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान ही उन्होंने सुरक्षा गार्ड्स की शिफ्ट वार तैनाती सहित वेयरहाउस की अन्य सुरक्षा व्यवस्था का भी निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए।

पूर्वांचल वासियों के लिए राहत, आईएमएस में 820 करोड़ खर्च कर बनाई जाएंगी एम्स जैसी सुविधाएं

वाराणसी। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) जैसी सुविधा के लिए आईएमएस बीएचयू को 820 करोड़ रुपये मिलेंगे। इस पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की सहमति बन चुकी है। इसका एलान आम बजट में संभव है। स्वास्थ्य मंत्रालय की सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव की मौजूदगी में सोमवार को नई दिल्ली में बैठक भी हो चुकी है। पहली बार मिलने वाले इतने बड़े बजट से आईएमएस बीएचयू में इलाज, पैथोलॉजी जांच और सर्जरी की व्यवस्थाएं विश्व स्तरीय बनाई जाएंगी। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, शिक्षामंत्री धर्मेंद्र प्रधान, एम्स निदेशक डॉ. एम श्रीनिवास की मौजूदगी में 22 नवंबर 2024 को नई दिल्ली में नए सिरे से एमओयू हुआ था। एम्स निदेशक ने बीएचयू आकर सुविधाओं का मूल्यांकन भी किया था।

विश्वस्तरीय व्यवस्थाएं बनाने का तैयार किया जा रहा खाका

अब इलाज, जांच, ओपीडी, आईसीयू, दवा सहित अन्य व्यवस्थाएं विश्वस्तरीय बनाने का खाका तैयार किया जा रहा है। विभाग और संकायवार सुविधाओं की कमी का मूल्यांकन कराया जा रहा है। देखा जा रहा है कि एम्स और आईएमएस बीएचयू की सेवाओं में किस तरह का कितना अंतर है। आईएमएस बीएचयू के निदेशक प्रो. एसएन संखवार ने बताया कि दिल्ली में सोमवार को बैठक हुई थी। इसमें बीएचयू के कुलसचिव प्रो अरुण भी शामिल हुए थे। बैठक में एम्स जैसी सुविधाओं पर चर्चा की गई। एम्स की तरह ही पहली बार आईएमएस बीएचयू को बड़ा बजट देने का खाका तैयार किया गया। इस बार के आम बजट में बजट की घोषणा हो सकती है।

कार्यालय, नगर पालिका परिषद भरवारी, जनपद – कौशाम्बी

पत्र संख्या : 3391 /न0पा0परि0भ0/निविदा/2024–25 **दिनांक : 22.01.2025**

निविदा सूचना

स्वायत्त निकाय/पब्लिक सेक्टर विभाग/राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के अन्तर्गत आने वाले किसी भी शासकीय विभाग में पंजीकृत ठेकेदार/फर्म को सूचित किया जाता है कि राज्य वित्त आयोग मद में प्राप्त धनराशि के सापेक्ष कार्यो की निविदा दिनांक 01.02.2025 को आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदा/टेण्डर कार्यालय नगर पालिका परिषद भरवारी में दिनांक 03.02.2025 को अपराहन 3:00 बजे अधोहस्ताक्षरी कक्ष में उपस्थित ठेकेदारों/फर्म के समक्ष खोली जायेगी। सम्बन्धित हस्ताक्षरयुक्त ब्लैक फार्म अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के लेखा लिपिक से दिनांक 23.01.2025 से दिनांक 01.02.2025 तक समय 12:00 बजे दिन तक वांछित धनराषि जमा कर प्राप्त की जा सकती है।

निविदा में सम्मिलित कार्यो का विस्तृत विवरण निम्नवत् है–

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (जी.एस.टी. सहित) (लाख में)	अनुमानित लागत (जी.एस.टी. रहित) (रू0 में)	बिड सिक्योरिटी (ई.एम.डी.) (रू0 में)	निविदा प्रपत्र का मूल्य (रू0 में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि
1	2	3	4	5	6	7
01	वार्ड नं0 03 गौतमबुद्ध नगर (बालकमऊ) में गौतम बौद्ध स्थल का सौंदर्यीकरण का कार्य।	8.63	731745.00	73175.00	865.00	01 माह
02	वार्ड नं0 03 गौतमबुद्ध नगर (बालकमऊ) में गौतम बौद्ध स्थल का निर्माण कार्य।	9.65	818202.00	81820.00	965.00	01 माह
03	वार्ड नं0 07 राम नगर में मौर्या बीज भण्डार से रेलवे लाइन तक मार्ग पर नव निर्माण कार्य।	9.81	831375.00	83138.00	985.00	01 माह
04	वार्ड नं0 07 राम नगर में प्रा0वि0 से नरेश कुशवाहा (सचिवालय) के मकान तक डामरीकरण का कार्य।	9.10	770850.00	77085.00	910.00	01 माह
05	वार्ड नं0 08 लियाकत अली नगर में रोही चौराहा पर ए तरफ आर.सी.सी. नाला का निर्माण कार्य।	9.62	815429.00	81543.00	965.00	01 माह
06	वार्ड नं0 08 लियाकत अली नगर में रोही चौराहा पर बी तरफ आर.सी.सी. नाला का निर्माण कार्य।	9.62	815429.00	81543.00	965.00	01 माह
07	वार्ड नं0 08 लियाकत अली नगर में रोही चौराहा पर सी तरफ सी.सी. नाला का निर्माण कार्य।	9.62	815429.00	81543.00	965.00	01 माह
08	वार्ड नं0 08 लियाकत अली नगर में रोही चौराहा पर डी तरफ सी.सी. नाला का निर्माण कार्य।	9.62	815429.00	81543.00	965.00	01 माह
09	वार्ड नं0 19 धर्मराज नगर में पल्हाना घाट में ए तरफ रिटेनिंगवॉल का निर्माण कार्य।	9.93	841986.00	84199.00	995.00	01 माह
10	वार्ड नं0 19 धर्मराज नगर में पल्हाना घाट में बी तरफ रिटेनिगंवॉल का निर्माण कार्य।	9.93	841986.00	84199.00	995.00	01 माह
11	वार्ड नं0 19 धर्मराज नगर में पल्हाना घाट में सी तरफ रिटेनिगंवॉल का निर्माण कार्य।	9.93	841986.00	84199.00	995.00	01 माह
12	वार्ड नं0 19 धर्मराज नगर में पल्हाना घाट में डी तरफ रिटेनिगंवॉल का निर्माण कार्य।	9.93	841986.00	84199.00	995.00	01 माह
13	वार्ड नं0 25 पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर (मूरतगंज) में राजू धुरिया के मकान से किशन प्रजापति के मकान तक मिट्टी, इण्टरलाकिंग सडक, एल नाली का निर्माण कार्य।	5.64	477890.00	47789.00	565.00	01 माह
14	वार्ड नं0 18 मोती लाल आजाद नगर में बिल्डिंग में बाउण्ड्रीवॉल का निर्माण कार्य।	9.94	842713.00	84271.00	995.00	01 माह
15	वार्ड नं0 18 मोती लाल आजाद नगर में अम्बेडकर मूर्ति में टाइल्स, सीढ़ी का निर्माण कार्य।	9.76	827504.00	82750.00	980.00	01 माह
16	वार्ड नं0 18 मोती लाल आजाद नगर में मालिन बस्ती में गुलाब के मकान से उमेश, रमेश, श्रीचन्द्र व महेश के मकान तक इण्टरलाकिंग व नाली का निर्माण कार्य।	9.71	823143.00	82314.00	975.00	01 माह
17	वार्ड नं0 19 धर्मराज नगर में पल्हाना घाट में मिट्टी कार्य।	7.66	649440.00	64944.00	770.00	01 माह
18	वार्ड नं0 23 डॉ0 ए0पी0जे0 अब्दुल नगर में (खलीलाबाद) में नया पम्प हाउस के पास पाइप लाइन का विस्तार कार्य।	7.98	676200.00	67620.00	780.00	01 माह
19	500 नग आर0सी0सी0 पिलर की आपूर्ति।	6.78	575000.00	57500.00	680.00	01 माह
20	500 नग आर0सी0सी0 पिलर की आपूर्ति।	6.78	575000.00	57500.00	680.00	01 माह
21	वार्ड नं0 04 श्यामा प्रसाद मुखर्जी नगर में स्थित उ0प्र0 विद्यालय असवां में बाउण्ड्रीवाल निर्माण कार्य।	3.77	319488.00	31949.00	380.00	01 माह
22	नगर पालिका परिषद भरवारी जोन कार्यालय धन्नी के विभिन्न वार्डो में सड़क व नाली का मरम्मत कार्य।	9.91	840000.00	84000.00	995.00	01 माह
23	नगर पालिका परिषद भरवारी जोन कार्यालय महेशपुर के विभिन्न वार्डो में सड़क व नाली का मरम्मत कार्य।	9.91	840000.00	84000.00	995.00	01 माह
24	नगर पालिका परिषद भरवारी जोन कार्यालय असवां के विभिन्न वार्डो में सड़क व नाली का मरम्मत कार्य।	9.91	840000.00	84000.00	995.00	01 माह
25	नगर पालिका परिषद भरवारी जोन कार्यालय बिसारा के विभिन्न वार्डो में सड़क व नाली का मरम्मत कार्य।	9.91	840000.00	84000.00	995.00	01 माह
26	नगर पालिका परिषद भरवारी कार्यालय के विभिन्न वार्डो में सड़क व नाली का मरम्मत कार्य।	9.91	840000.00	84000.00	995.00	01 माह
27	वार्ड न0 18 मोती लाल आजाद नगर में रिन्कू त्रिपाठी के मकान से संतोष मौर्या के मकान तक व मेन रोड तक इण्टरलाकिंग सड़क व नाली का निर्माण कार्य।	5.01	425136.00	42514.00	505.00	01 माह
28	वार्ड न0 03 गौतमबुद्ध नगर (बालकमऊ) में लल्लू के घर से पृथ्वी के घर तक मिट्टी, इण्टरलाकिंग सड़क व एल नाली का निर्माण कार्य।	1.51	127646.00	12765.00	155.00	01 माह
29	वार्ड न0 12 कृष्णा नगर (पाण्डेयमऊ) में बच्चा लाल के घर से नीबू लाल के घर तक के0सी0 ड्रेन रिपेयर का कार्य।	0.98	83330.00	8330.00	100.00	01 माह
30	वार्ड न0 24 शहीद गुलाब सेन नगर में जय सिंह के घर से राजा गुप्ता के मकान तक सी0सी0 रोड व नाली रिपेरिंग का कार्य।	1.68	142335.00	14234.00	170.00	01 माह

नियम/शर्तें:

1. उपरोक्त निविदा की विस्तृत जानकारी नगर पालिका परिषद, भरवारी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में सम्पर्क कर उपरोक्त निविदा के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्राप्त किया जा सकता है।
2. उपरोक्त निविदा में सम्मिलित निर्माण कार्यो में निदेशक महोदया, स्थानीय निकाय निदेशालय, लखनऊ के द्वारा निर्गत निर्देश पत्र संख्या टी.सी./314/8/डी.एल.बी./2020 दिनांक 01.01.2021 में निर्माण कार्यो हेतु उल्लिखित दिशा निर्देशो तथा अपर मुख्य सचिव महोदय, नगर विकास विभाग अनुभाग–9 उ0प्र0 शासन के द्वारा नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत में निर्माण/विकाय कार्यो हेतु मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) विषयक निर्गत शासनादेश संख्या 1319/नौ–9–21–45ज/21 नगर विकास विभाग, अनुभाग–9 लखनऊ दिनांक 30 जून, 2021 में वर्णित समस्त निर्देशो के साथ ही भिन्न–भिन्न समय में उच्चाधिकारियो के द्वारा निर्गत किये गये तथा भविष्य में निर्गत होने वाले समस्त दिशा निर्देशो का अनुपलन करना होगा।
3. उपरोक्त निविदा में स्वायत्त निकाय/पब्लिक सेक्टर विभाग/राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के अन्तर्गत आने वाले किसी भी शासकीय विभाग में पंजीकृत ठेकेदार/फर्म से आमंत्रित की गयी है। निविदा के साथ किसी भी शासकीय विभाग में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024–25 में पंजीकृत होने के अद्यतन प्रमाण पत्र के मूल प्रति के साथ ही ठेकेदार/फर्म के द्वारा अपना अद्यतन वैध चरित्र प्रमाण पत्र **(T-4)**, हैसियत प्रमाण पत्र **(T-5)**, निर्धारित मूल्य (रू0 100) के स्टाम्प पेपर पर कार्य के नाम के स्पष्ट उल्लेख के साथ घाषणा पत्र **(T-6)**, ळैज रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, श्रम विभाग में पंजीकृत होने के प्रमाण पत्र की मूल प्रति निविदा प्रपत्र में स्पष्ट रूप से पठनीय हो, बन्द लिफाफे में जमा करना अनिवार्य होगा (जिससे निविदा में संलग्न प्रमाण पत्रो का परीक्षण किया जा सकें) अन्यथा सम्बन्धित की निविदा को निरस्त समझी जायेगी।
4. निविदा में सम्मिलित कार्यो के समान प्रकृति से जुड़े कार्य विषयक किसी एक या एक से अधिक शासकीय विभाग का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। सम्बन्धित कार्य के लिए वही अनुभव प्रमाण पत्र मान्य होगा जो सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म के द्वारा निविदा हेतु प्रस्तावित उपरोक्त कार्य की धनराशि या उससे अधिक धनराशि के संतोषजनक ढ़ग से कार्य को पूर्ण करने से सम्बन्धित विगत तीन वित्तीय वर्ष के अन्दर के हो तथा यही भी कार्य के प्रकृति के अनुरूप कार्य कराये जाने का अनुभव सम्बन्धित कार्य की निविदा में मान्य होगा।
5. निविदा में सम्मिलित डी.बी.एम. एवं बी.सी. सड़क के निर्माण हेतु सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म के स्वयं के यांत्रिक उपकरण एवं स्वयं के प्लान्ट के स्थान विषयक प्रमाण पत्र संलग्न करने के साथ पूर्व में उपरोक्त प्रकृति के कार्य कराये जाने का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6. निविदा में सम्मिलित विद्युतीकरण कार्य हेतु निविदादाता ठेकेदार/फर्म का विद्युतीकरण कार्य कराये जाने का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा तथा उपरोक्त विद्युतीकरण कार्य में अधिष्ठापित होने वाली लाइटे **CAT-3** कटैगरी की (फिलिपस या हैवेल्स या क्राम्पटन मे से कोई) जिसके अनुरक्षण की अवधि पांच वर्ष की शर्त के साथ हो मान्य होगी।
7. निविदा में सम्मिलित पेयजल/पाईप लाइन से जुड़े कार्यो हेतु पूर्व में सामान धनराशि या उससे अधिक धनराशि के कराये गये कार्य का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
8. निविदा पर सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार द्वारा सभी प्रपत्र प्रत्येक दशा में दृश्य एवं स्पष्ट रूप से पठनीय होने चाहिये, डाक्यूमेंट दृश्य एवं स्पष्ट रूप से पठनीय नही होगे तो सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार की निविदा स्वतः निरस्त मानी जायेगी।
9. निविदा में सम्मिलित प्रत्येक कार्य का निविदा शुल्क/जमानत धनराशि पृथक–पृथक जमा करना अनिवार्य होगा तथा निविदा शुल्क की धनराशि फर्म/ठेकेदार के खाते या फर्म के प्रोपराइटर के खाते से जमा करने विषयक ऑनलाइन रसीद ही मान्य होगी।
10. निविदा शुल्क की धनराशि इण्डियन बैंक शाखा भरवारी **IFSC** कोड **IDIB000B770** खाता संख्या 21620409262 जो **NP Bharwari Kaushambi** के नाम से खुले बैंक खाते में जमा करना होगा तथा जमा धनराशि का प्रमाण निविदा खोलने के पूर्व ठेकेदारी विषयक स्वप्रमाणित प्रपत्रो व जमानत धनराशि की मूल प्रति के साथ सील बन्द लिफाफे में देना अनिर्वाय होगा, तभी निविदा मान्य होगी।
11. नगर पालिका परिषद भरवारी, कौशाम्बी के द्वारा पूर्व में आमंत्रित निविदा में सम्मिलित ऐसे ठेकेदार/फर्म जिनके पक्ष में स1 दर होने के कारण स्वीकृत पत्र जारी किया गया था, परन्तु अभी तक स्वीकृत पत्र जारी होने के बाद भी अनुबन्ध नही कराया गया है तो सम्बन्धित की निविदा पर विचार नही किया जायेगा तथा यह भी कि यदि अनुबन्ध कराया गया है तो कोई विभागीय समस्या होने के कारण उपरोक्त स्वीकृत कार्य सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म के द्वारा कार्य प्रारम्भ करने का इच्छुक होने पर भी वर्तमान में कार्य प्रारम्भ किया जाना सम्भव नही है, ऐसे कार्यो को छोड़कर सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म के पक्ष में स्वीकृत तीन या तीन से अधिक कार्य निविदा के प्रकाशन तिथि तक अपूर्ण/अधूरे है, कि निविदा पर विभाग द्वारा कोई विचार नही किया जायेगा।
12. निविदा खोलने से पूर्व निविदा प्रपत्र के साथ 10% जमानत धनराशि का **FDR** जो अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद भरवारी, कौशाम्बी के पदनाम से बन्धक हो, को मूल रूप में सम्बन्धित तकनीकी बिड खुलने के पूर्व ठीकेदार/फर्म के द्वारा निविदा के साथ स्कैन किये गये ठेकेदारी विषयक वांछित प्रमाण पत्रो की स्वप्रमाणित प्रति के साथ मूल रूप में जमा करना अनिवार्य होगा, अयंथा सम्बन्धित कार्य की तकनीकी निविदा पर विचार नही किया जायेगा। यह भी किसी भी कार्य की निविदा के साथ संलग्न जमानत धनराशि की **FDR** की प्रति मात्र एक कार्य की निविदा में ही मान्य होगी अर्थात जमानत धनराशि के **FDR** में उल्लिखित धनराशि अधिक होने पर भी उपरोक्त जमानत धनराशि का **FDR** किसी अन्य कार्य की निविदा में मान्य नही होगी।
13. शासनादेश संख्या– 11593/नौ–5–2021–142सा/2021 नगर विकास अनुभाग–5, लखनऊ दिनांक 07.01.2022 के अनुसार अनुबंध गठन के समय 10 प्रतिशत बिलो (**Below**) दर तक 03.00 प्रतिशत तथा 10 प्रतिशत से अधिक बिलो (**Below**) दर पर 1.00 प्रतिशत प्रति 0.50 प्रतिशत कम पर सिक्योरिटी/परफार्मेंस गारण्टी का अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद भरवारी, कौशाम्बी के पदनाम से बंधक युक्त थक्त निविदा स्वीकृत पत्र निर्गत होने के एक सप्ताह के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत कर नियमानुसार अनुबन्ध का गठन कराना अनिवार्य होगा अन्यथा यह मानते हुए की आपके द्वारा निविदा बाधित करने के उद्देश्य से निविदा डाली गयी है मानते हुए आपके पक्ष में निर्गत स्वीकृत पत्र निरस्त करते हुए आपके निविदा के साथ जमा की गयी 10% जमानत धनराशि विभाग के पक्ष में जब्त करते हुए उपरोक्त निविदा में **L2** दरदाता की निविदा के पक्ष में स्वीकृत करने हेतु कार्यवाही की जायेगी।
14. निविदा में किसी प्रकार की त्रुटि तथा सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी एवं अपूर्ण पाये जाने पर आशिंक रूप से या सम्पूर्ण निविदा प्रक्रिया को निरस्त करने अथवा संशोधन करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी में निहित होगा।
15. निविदा में सम्मिलित निर्माण कार्यो हेतु जमा की गयी जमानत धनराशि को शासन द्वारा निर्गत मानक संचालन प्रक्रिया (एस.ओ.पी.) का निर्धारण पत्र संख्या 1319/नौ–9–21–45ज/21 दिनांक 30 जून, 2021 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार एक वर्ष तक कार्य संतोषजनक विषयक आख्या के अनुसार अवमुक्त किया जायेगा।
16. निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् नियमानुसार निर्धारित मूल्य के स्टाप पेपर एवं निर्धारित प्रारूप पर स्वयं के व्यय पर सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म के द्वारा अनुबन्ध कराना होगा।
17. प्रत्येक स्वीकृत निर्माण कार्य के अनुबन्ध से पूर्व ठेकेदार को श्रम विभाग में अधिष्ठान पंजीयन एंव निर्माण श्रमिक पंजीयन करवाना अनिवार्य होगा।
18. स्वीकृत कार्य के पूर्व, कार्य के दौरान एंव कार्य पूर्ण होने के बाद की कलर फोटो कार्यालय में उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
19. कार्य समाप्त करने की दी गयी समयावधि का आधा समय बीत जाने या अधिकतम अनुबन्ध होने के एक माह के अन्दर सम्बन्धित ठेकेदार के द्वारा कार्य प्रारम्भ नही किया जाता है, तो उसके पक्ष में स्वीकृत निविदा निरस्त कर दिया जायेगा।
20. निर्माण कार्य की गुणवत्ता की जांच/सत्यापन हो जाने के उपरान्त ही नियमानुसार भुगतान की कार्यवाही की जायेगी। यदि कार्य की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी पायी जायेगी तो सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म के द्वारा जमा जमानत/परफार्मेंस धनराशि जब्त करते हुए सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म के विरूद्ध अन्य विभागीय कार्यवाही की जायेगी।
21. निविदाओं में अंकित कार्यो की मात्रा में परिवर्तन हो सकता है, जिसके लिये ठेकेदार/फर्म का कोई दावा मान्य नही होगा।
22. निविदा आमंत्रणकर्ता को आईटीबी के क्लॉज–9 के अनुसार परिशिष्ट/शुद्धि पत्र जारी करने का अधिकार है जो किसी भी समाचार पत्र मे प्रकाशित नही किया जायेगा। सभी संभावित निविदादाताओं को सलाह दी जाती है कि वय नियमित रूप से निविदा पर निगरानी रखें। अधिक जानकारी के लिए कृपया कार्यालय से सम्पर्क करें।
23. उपरोक्त निविदा को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार अद्योहस्ताक्षरी में निहित होगा तथा समस्त विवाद का न्यायिक क्षेत्र जनपद कौशाम्बी होगा।

लेखा लिपिक	अवर अभियन्ता (सिविल)	अधिषाशी अधिकारी	अध्यक्ष
नगर पालिका परिशद भरवारी, कौ□ाम्बी	नगर पालिका परिशद भरवारी, कौ□ाम्बी	नगर पालिका परिशद भरवारी, कौ□ाम्बी	नगर पालिका परिशद भरवारी, कौ□ाम्बी

डीजीपी प्रशांत कुमार ने लगाई संगम में डुबकी, तैयारियों का लिया जायजा

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ने बुधवार को गंगा–यमुना और सरस्वती के संगम में डुबकी लगाई। इसके बाद उन्होंने भगवान भास्कर को अर्घ्य देने के साथ ही मां गंगा की पूजा आराधना की। दर्शन करने के बाद उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ भ्रमण कर मेले में सुरक्षा का जायजा लिया। उनका ज्यादातर जोर जल पुलिस और डूबने से बचाने वालों और महाकुंभ में आग से बचाव और इसके प्रति जागरूकता पर रहा। जीवनदायिनी माँ गंगा की कृपा से समस्त श्रद्धालुओं की साधना सुगमता और सुरक्षा पूर्वक संपन्न हो, उनकी आध्यात्मिक अपेक्षाओं को पूर्णता की प्राप्ति हो, यही प्रार्थना है।माँ गंगा का आशीर्वाद संपूर्ण सृष्टि पर बना रहे, सभी के मनोरथ पूर्ण हों।

महाकुंभ में पहली बार दिखाई जाएगी यह एनिमेटेड फिल्म, जानें कब और कहां होगी इसकी स्क्रीनिंग

प्रयागराज। भव्य और दिव्य महाकुंभ में इस बार कई नई पहल की जा रही हैं। इसी क्रम में महाकुंभ मेले के इतिहास में पहली बार किसी एनिमेटेड फिल्म का प्रदर्शन होने जा रहा है। महाकुंभ मेले में एक ऐतिहासिक पहल के तहत इंडो–जापानी एनिमेटेड फिल्म 'रामायण – द लीजेंड ऑफ प्रिंस राम' का हिंदी संस्करण प्रदर्शित किया जाएगा। यह विशेष स्क्रीनिंग मुख्य अतिथि और प्रदेश सरकार में समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण की उपस्थिति में 22 जनवरी बुधवार को सुबह 10रू00 बजे दिव्य प्रेम सेवा शिविर, सेक्टर 6, नेत्र कुंभ के पास होगी। फिल्म भगवान श्रीराम की अद्वितीय गाथा, उनकी निष्ठा और अधर्म पर धर्म की विजय को जीवंत रूप में प्रस्तुत करती है। यह महाकुंभ मेले में बच्चों के लिए खास तौर पर आयोजित की जा रही है। आयोजनकर्ताओं के अनुसार, यह फिल्म परिवारों और हर आयु वर्ग के दर्शकों के लिए प्रेरणादायक और मनोरंजक होगी। यह फिल्म 24 जनवरी 2025 को देशभर में रिलीज की जाएगी। महाकुंभ में इसका प्रदर्शन इसे और अधिक विशेष बनाता है। इस अनुभव का आनंद लेने के लिए श्रद्धालु सुबह 10 बजे दिव्य प्रेम सेवा शिविर, सेक्टर 6 में आ सकते हैं।

आयरलैंड के सर्वर से चल रही होटल की फर्जी वेबसाइट, कंपनी ने ब्योरा देने से किया इन्कार

प्रयागराज। महाकुंभ में शहर के नामी होटलों में बुकिंग के नाम पर आए दिन पर्यटकों को ठगी को शिकार बनाया जा रहा है। होटल कान्हा श्याम के नाम से चल रही फर्जी वेबसाइट को लेकर साइबर पुलिस को अहम सुराग मिला है। पता चला कि यह इस वेबसाइट का सर्वर आयरलैंड से चल रहा है। हालांकि, साइबर पुलिस ने वेबसाइट का ब्योरा मांगा तो कंपनी ने देने से इन्कार कर दिया। 16 दिसंबर को होटल कान्हा श्याम के महाप्रबंधक रुपेश कुमार सिंह ने उनके होटल के नाम से फर्जी वेबसाइट ंदीीलंउ.ीवजमसंसससीइंक.बवउ बनाकर बुकिंग करने पर सिविल लाइंस थाने में केस दर्ज कराया था। केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने आयरलैंड डोमेन कंपनी को मेल के माध्यम से पूछा था कि उक्त वेबसाइट किस नाम और किस शहर से संचालित हो रही है। साथ ही होस्ट करने वाले के बारे में भी जानकारी मांगी गई थी। लेकिन, कंपनी की ओर से सूचना देने से इन्कार कर दिया गया है। ऐसे में अब साइबर पुलिस गृह मंत्रालय की मदद से साइबर अपराधी का रिकॉर्ड खंगालेगी। ताकि होटल कान्हा श्याम के नाम पर चल रही फर्जी वेबसाइट के अपराधी को पकड़ा जा सके। वहीं, घटना के एक माह से अधिक समय के बाद भी होटल के नाम से बनी फर्जी वेबसाइट ंदीीलंउ.ीवजमसंसससीइंक.बवउ चल रही है। साइबर पुलिस अफसरों का कहना है कि अन्य दर्जनों वेबसाइटों को बंद करवा दिया गया है। इस वेबसाइट को भी बंद करने की प्रक्रिया चल रही है। वहीं, साइबर पुलिस ने 15 और फर्जी वेबसाइटों को चिह्नित किया है, जिनके जरिये महाकुंभ में टेंट, होटल और लॉज बुक कराने के नाम पर श्रद्धालुओं को चपत लगाई जा रही है। साइबर पुलिस इनकी जांच कर रही है।

श्रद्धालुओं को राम नाम लेखन का ऋण दे रहा है श्रीराम बैंक, लेकिन कुछ शर्तो के साथ

प्रयागराज। यह बैंक है...मगर पैसों का लेनदेन नहीं करता। इसका नाम है, श्रीराम बैंक। यह श्रद्धालुओं को प्रभु राम का नाम लिखने का ऋण देने वाला बैंक है। अब तक यहां से करोड़ों राम नाम लिखने का ऋण दिया जा चुका है। यहां जमा करने से ज्यादा ऋण लेने की होड़ है। इस बैंक की शाखा मेला क्षेत्र के सेक्टर छह में 22 दिसंबर को खोली गई थी। इसके

कर्ताधर्ता आशुतोष वार्ष्णेय बताते हैं कि यह बैंक करीब 150 वर्ष पुराना है। इसकी ईएमआई (मासिक किस्त) भी वसूली जाती है। इसका लेखा–जोखा भी रखा जाता है। आशुतोष बताते हैं कि न्यूनतम ऋण डेढ़ लाख का है। इसके आगे कितना ऋण लेना है, यह श्रद्धालु पर निर्भर है। राम नाम लिखन के लिए छपी–छपाई मुफ्त कॉपियां दी जाती हैं। इनके रिक्त खानों में ही प्रभु का नाम लिखना होता है। बुकलेट के हर पेज पर राम नाम की गणना भी दर्ज होती चलती है। कॉपियां भर जाने के बाद श्रद्धालु उन्हें राम बैंक में जमा करा देते हैं। बाद में यही कॉपियां दूसरे के लिए ऋण का काम करती हैं। किसी श्रद्धालु को 1.5 लाख राम नाम का ऋण दिया गया है तो इसे वह किस्त के रूप में लिखकर लौटाता है। अभी तक 25 से अधिक लोग करोड़ों राम नाम लिखने का कर्ज ले चुके हैं। महाकुंभ के बाद इसका आधिकारिक डाटा जारी किया जाएगा। राम नाम का लेखन हिंदी के साथ अंग्रेजी, उर्दू और बांग्ला में भी कर सकते हैं। यह बैंक छह से लेकर 80 साल तक के लोगों को ऋण देता है। शर्त यह है कि इसे लिखने वाले को मांस–मदिरा के साथ लहसुन–प्याज का सेवन भी छोड़ना पड़ता है। मेला शाखा के प्रचारक राजकुमार बताते हैं कि ऋण लेने के लिए लाभार्थी के पास केवल अपना एक फोटो होना चाहिए, जिससे उसकी पहचान हो सके। राम नाम का ऋण लेने वालों में कई विदेशी श्रद्धालु भी हैं। इन्हीं में हैं, नीदरलैंड के हैंक केल्मैन और अमेरिका में प्रवास कर रहीं सोनल सिंह। इन्होंने एक–एक करोड़ का ऋण लिया है। हैंक अब रामकृष्ण दास हो चुके हैं। बैंक की शुरुआत को लेकर आशुतोष वार्ष्णेय बताते हैं कि यह उनकी पांचवीं पीढ़ी है। चौक के व्यापारियों ने इसकी शुरुआत की थी। वे अपनी कमाई का 10 फीसदी सामाजिक कार्यों में खर्च करते थे। इसी से राम नाम लेखन शुरू हुआ। पहले उनके बही खातों में लिखा जाता था। फिर, बुकलेट आ गई। अब ई–राम भी आ चुका है। ई–राम सोशल मीडिया अकाउंट के जरिये लेनदेन के लिए उपयोग किया जाता है।

यीडा और यूपीडा के पंडाल में यूपी औद्योगिक विकास की स्पष्ट झलक

महाकुम्भ नगर। एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर बन कर तैयार है, जहां से जल्द ही हवाई उड़ान शुरू होगी। वहीं नोएडा में इंटरनेशनल फिल्म सिटी भी जल्द ही स्थापित होने जा रही है। यही नहीं गंगा एक्सप्रेसवे निर्माण के साथ ही देश के सर्वाधिक 50 प्रतिशत से अधिक एक्सप्रेसवे के नेटवर्क वाला प्रदेश अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश बनने जा रहा है। इसके साथ प्रदेश के औद्योगिक विकास में 2017 के बाद से अब तक हुए कई क्रांतिकारी बदलाव एवं विकास से देश ही नहीं बल्कि विश्व के कोने–कोने से आने वाले श्रद्धालुओं को अवगत कराने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता नन्दी ने महाकुम्भ मेला क्षेत्र में सोमवार को यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) एवं उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के पवेलियन एवं प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। नन्दी ने कहा कि 2017 के पहले उत्तर प्रदेश की पहचान बीमारू राज्य के रूप में होती थी। जहां कानून व्यवस्था ध्वस्त थी। उद्यमी प्रदेश में उद्योग लगाने एवं निवेश

करने से डरते थे। पलायन कर रहे थे। 2017 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद प्रदेश की दशा और दिशा दोनों में बदलाव हुआ। आज उत्तर प्रदेश देश का ग्रोथ इंजन बनने की ओर अग्रसर है। वहीं उत्तर प्रदेश निवेशकों का प्रमुख गंतव्य बन कर उभरा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जेवर के निर्माण से पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में विकास की एक नयी लहर आ गई है। साथ ही साथ यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण द्वारा संचालित विभिन्न औद्योगिक, संस्थागत योजनाओं से क्षेत्र व प्रदेश में रोजगार व विकास के नए अवसर सृजित हुए हैं। यीडा के पंडाल में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में बन रहे मेडिकल डिवाइसेज पार्क, सेक्टर 29 में विकसित किए जा रहे अपेरल पार्क, सेक्टर 33 में स्थापित टॉय पार्क, सेक्टर 10 व सेक्टर 28 में बनने वाले सेमी कंडक्टर पार्क, सेक्टर 32 व 33 की एमएसएमई, हैण्डीक्राफ्ट पार्क सहित सभी औद्योगिक सेक्टर्स की परियोजनाओं की प्रगति देखने को मिलेगी। पंडाल में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर के भव्यता एवं दिव्यता से भी लोगों को परिचय कराया जाएगा, जो एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। जिसका उद्घाटन जल्द ही होने जा रहा है। साथ ही यहां पर सेक्टर 21 में स्थापित होने वाली इंटरनेशनल फिल्म सिटी परियोजना की भी जानकारी लोगों को मिलेगी। मैसर्स बेबव्यू भूटानी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित की जा रही इंटरनेशनल फिल्म सिटी परियोजना का भव्य स्टाल भी दर्शाया गया है। जिसमें परियोजना के स्वरूप, डिजाइन आदि के संबंध में संबंधित अधिकारियों द्वारा जानकारी दी गई। फिल्म सिटी परियोजना में विकाश कार्य जल्द ही शुरू होने वाला है। मंत्री नन्दी ने प्रियागोल्ड के स्टाल, पतंजलि के स्टाल का भी फीता काटकर उद्घाटन किया। इस अवसर पर स्टाफ ऑफिसर नंदकिशोर सुन्द्रियाल, हरि प्रताप तहसीलदार, दामोदर मिश्रा भूटानी ग्रुप, शिवेंद्र मिश्रा, विवेकानंद मिश्रा, अंकित सिंह आदि उपस्थित रहे। उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के पंडाल में उत्तर प्रदेश के एक्सप्रेस प्रदेश बनने के सफर को दर्शाया गया है। जिसमें बुन्देलखण्ड एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, आगरा–लखनऊ एक्सप्रेसवे के साथ ही उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के प्रगति को दर्शाया गया है। देश में कुल एक्सप्रेसवे का सबसे अधिक एक्सप्रेसवे वाला राज्य उत्तर प्रदेश किस प्रकार बनने जा रहा है। इस हकीकत को स्पष्टता से दर्शाया गया है। यूपीडा के पंडाल में उद्घाटन अवसर पर ओएसडी सुनील कुमार सिंह, इंद्र मोहन लाम्बा, एक्सईएन मनोज कुमार के साथ ही अन्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

रेल राज्यमंत्री ने व्यवस्था का निरीक्षण किया

प्रयागराज। केंद्रीय राज्य मंत्री, रेल एवं जल शक्ति, वी. सोमन्ना ने प्रयागराज जंक्शन स्टेशन पर महाकुंभ –2025 के लिए किए गए व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया । इस अवसर पर महाप्रबंधकध्उत्तर मध्य रेलवे, उपेन्द्र चंद्र जोशी एवं मण्डल रेल प्रबंधकध्प्रयागराज, हिमांशु बडोनी उनके साथ थे । केंद्रीय राज्य मंत्री, रेल एवं जल शक्ति, वी. सोमन्ना ने प्रयागराज जंक्शन स्टेशन पर मेडिकल ऑब्जर्वेशन कक्ष, यात्री आश्रय एवं मेला टॉवर का निरीक्षण किया । निरीक्षण के दौरान यात्री आश्रय में श्रद्धालुओं से भी बातचीत कर उनका हालचाल पूछा एवं श्रद्धालुओं को जानकारी उपलब्ध कराने के लिए 22 भाषाओं में तैयार किए गये लीफलेट की प्रशंसा की । केंद्रीय राज्य मंत्री, रेल एवं जल शक्ति ने निरीक्षण के उपरांत मेला टॉवर में आयोजित प्रेस वार्ता में मीडिया कर्मियों को संबोधित किया । प्रेस वार्ता में

मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुये कहा कि मकर संक्रांति पर्व पर रिकार्ड 148 विशेष ट्रेनें चलाई गईं । मौनी अमावस्या के दिन 150 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाने की योजना है एवं मौनी अमावस्या पर 01 दिन पूर्व से 02 दिन बाद तक कुल 400 से अधिक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी । यात्रियों की सुविधा के लिए कुंभ विशेष ट्रेनें चलाने के लिए करीब 200 रेक उपलब्ध कराए गए हैं । महाकुंभ–2025 के दौरान बेहतर व्यवस्थाओं के लिए अन्य क्षेत्रीय रेलवे से 10,000 से अधिक कर्मचारियों को तैनात किया गया है एवं स्टेशनों पर करीब 10,000 राजकीय रेलवे पुलिस एवं रेल सुरक्षा बल के जवानों को तैनात किया गया है। वी. सोमन्ना ने प्रेस वार्ता के दौरान यह भी कहा कि महाकुंभ –2025 मे राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार के डबल इंजन ने अभूतपूर्व सुविधाएं उपलब्ध करायी हैं। विश्व स्तर का यह भव्य आयोजन माननीय प्रधानमंत्री एवं मुख्यमन्त्री के कुशल नेतृत्व में आयोजित हो रहा है, जिसके लिए पूरा देश गौरवान्वित महसूस कर रहा है । उन्होंने रेल की अभूतपूर्व व्यवस्था के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को भी धन्यवाद दिया। मीडिया के द्वारा कर्नाटक के सबसे बड़े उत्सव पर पूछे गए प्रश्न के जवाब में केंद्रीय राज्य मंत्री, रेल एवं जल शक्ति ने कहा कि कर्नाटक में दशहरा एक दिन का होता है और यहाँ दशहरा हर दिन मनाया जा रहा है । केंद्रीय राज्य मंत्री, रेल एवं जल शक्ति ने कहा कि स्टेशनों पर सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं । रेलवे सुरक्षा बल, राजकीय रेलवे पुलिस, एनडीआरएफ एवं एसडीआरएफ मिलकर कार्य कर रहे हैं ।महाकुंभ –2025 के दौरान 3000 स्पेशल गाडियाँ सहित 13000 से अधिक रेल गाडियाँ चलायी जाएंगी जबकि गत कुम्भ मेला में 7000 गाड़ियों का संचालन किया गया था । प्रयागराज जंक्शन पर निरीक्षण के दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री, रेल एवं जल शक्ति ने यात्री सेवा एवं यात्री हितों की दिशा में किए जा रहे सभी रेल कार्यों तथा निर्माणाधीन परियोजनाओं की विस्तृत जानकारी प्राप्त की एवं आवश्यक निर्देश दिए । यात्री आश्रयों में कलर कोडिंग, साइनेज, खानपान, प्रकाश, पेयजल, चिकत्सा बूथ, जन सुविधाएँ, सुरक्षा व्यवस्था को बारीकी से देखा । महाकुंभ –2025 के दौरान स्टेशन पर यात्रियों के प्रवेश और निकास योजना पर जानकारी के साथ स्टेशन पर यात्रियों को दिशावार यात्रानुसार गेट से प्रवेश से लेकर गाड़ी तक भेजने की व्यवस्था, यात्रियों को टिकट काउंटर पर भेजना, यात्रियों को टिकट उपलब्ध करवाना, गाड़ियों की जानकारी देना, भीड़ को नियंत्रित करना, यात्रियों के प्लेटफॉर्म पर पहुँचने पर उन्हें सुरक्षित रूप से गाड़ी के अंदर भेजना और गाड़ी में पर्याप्त यात्री हो जाने पर गाड़ी को प्रस्थान करवाने के लिए प्लेटफार्म से कंट्रोल टावर को सूचना भेजना और अन्य विभागों से समन्वय की कार्यप्रणाली पर भी जानकारी ली और इस दिशावार व्यवस्था की तारीफ की ।केंद्रीय राज्य मंत्री, रेल एवं जल शक्ति, वी. सोमन्ना ने प्रयागराज जंक्शन की सुरक्षा प्रणाली और आपात स्थिति के लिए की गई तैयारियों की भी जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान रैपिड एक्शन टीम एवं क्विक रेस्पोंस टीम और फायर फाईटिंग टीम के कर्मचारियों से बातचीत कर उनकी कार्यप्रणाली को परखा, और बेहतर कार्य करने के लिए आवश्यक निर्देश भी दिए । वी. सोमन्ना ने निरीक्षण के अगले क्रम में 18 स्क्रीन से सुसज्जित सीसीटीवी कक्ष युक्त मेला टॉवर का निरीक्षण किया । मेला टॉवर में तैनात कर्मचारियों से सीसीटीवी के विषय में जानकारी ली और बेहतर समन्वय और त्वरित कार्यप्रणाली के लिए आवश्यक निर्देश दिए ।

इस्राइली मशीनगन से लेकर अमेरिकी स्नाइपर राइफल तक, मेले में देखिए पुलिस की ताकत

प्रयागराज। क्या आपको मालूम है कि उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ते के पास इस्राइल की ग्लॉक 17 मशीनगन है। बिना मूव किए ही इस हाईटेक गन के जरिये चारों दिशाओं में दुश्मनों को ढेर किया जा सकता है। इसी तरह अमेरिका में बनी स्नाइपर राइफल भी है। इससे 1.8 किमी की दूरी पर स्थित दुश्मन को भी मार गिराया जा सकता है। यूपी पुलिस की ऐसी कई ताकतों को करीब से देखने और जानने का मौका महाकुंभ में मिल रहा है। त्रिवेणी मार्ग स्थित पुलिस गैलरी में अत्याधुनिक हथियारों, सुरक्षा उपकरणों के साथ–साथ उत्तर प्रदेश पुलिस की विभिन्न इकाइयों की कार्यप्रणाली का भी प्रदर्शन किया गया है। दो दिन पहले ही मुख्यमंत्री योगी ने गैलरी का उद्घाटन किया है। गैलरी में पुलिस इकाइयों की कार्यप्रणाली और उनके पास मौजूद हाईटेक हथियारों व सुरक्षा उपकरणों के साथ तीन नए कानून के बारे में भी जानकारी दी गई है। गैलरी में प्रवेश करते ही अभियोजन निदेशालय ने अपनी कार्यप्रणाली व उपलब्धियां

को दर्शाने वाला कॉर्नर बनाया है तो इसके ठीक बगल में कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाओं के कॉर्नर में कारागार में होने वाली गतिविधियों के बारे में जानकारी दी गई है। इन्हीं से सटे तीन अलग–अलग कॉर्नर में न्यायालय, प्रशिक्षण निदेशालय और राज्य आपदा मोचन बल (एसडीआरएफ) ने अपने काम करने के तरीकों और उपकरणों का प्रदर्शन किया है। इसके बाद बारी आती है एसटीएफ और एटीएस के कॉर्नर की। यहां दोनों इकाइयों की ओर से उन हाईटेक हथियारों का प्रदर्शन किया गया है, जिसका उपयोग दोनों एजेंसियां काउंटर ऑपरेशन के दौरान करती हैं। इनमें इस्राइल ग्लॉक मशीनगन के साथ अमेरिकी स्नाइपर राइफल, रूस की एक–47 एसॉल्ट गन, ऑस्ट्रियाई ग्लॉक–17 पिस्टल के अलावा स्वदेशी कंपैक्ट ग्रेनेड रॉकेट लांचर और मोर्टार लांचर आदि शामिल हैं। इसी तरह यातायात निदेशालय, महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन, पुलिस थाना, सोशल मीडिया सेंटर, पुलिस तकनीकी सेवाएं और विधि विज्ञान प्रयोगशाला आदि इकाइयों के बारे में भी बताया गया है। गैलरी के पुलिस दूरसंचार इकाई के कॉर्नर में आने पर वर्तमान महाकुंभ में इस्तेमाल होने वाली मोबाइल संचार व्यवस्था का मॉडल देखने को मिलता है। इसके साथ ही 86 वर्ष पुरानी संचार व्यवस्था के मॉडल को देखकर यह जानकारी मिलती है कि 1938 में पहली बार हरिद्वार कुंभ में तीन हाथियों पर उपकरण बांधकर वायरलेस टेक्नोलॉजी पर आधारित मोबाइल संचार व्यवस्था का इस्तेमाल करने वाला उत्तर प्रदेश पहला राज्य था। गैलरी में अभिसूचना इकाई के अंतर्गत आने वाले सुरक्षा विभाग का काउंटर भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहां उन हाईटेक उपकरणों को दर्शाया गया है जो वीवीआईपी के अलावा महत्वपूर्ण धार्मिक सरकारी प्रतिष्ठानों की सुरक्षा के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें एएस चेक व बम डिस्पोजल स्क्वॉड की की ओर से इस्तेमाल होने वाले उपकरणों को दर्शाया गया है। इनमें से बंदूक जैसा दिखने वाला वाटर जेट डिसरप्टर भी है। इसकी खासियत यह है कि किसी भी संदिग्ध सूटकेस बैग या बक्से के मिलने पर यह उसे बिना छुए नष्ट कर सकता है।

महा कुम्भ मेले में योगी कैबिनेट की महा बैठक

महाकुंभ नगर। बुधवार को प्रयागराज में यूपी कैबिनेट की ऐतिहासिक बैठक में विकास कार्यो को मंजूरी मिली। जिसमें अभियोजन निदेशालय की स्थापना के लिए मंजूरी। प्रयागराज, वाराणसी और आगरा नगर निगमों के लिए म्युनिसिपल बॉन्ड जारी करने की स्वीकृति। 62 राजकीय आईटीआई का उन्नयन और

5 ब्य्य्ज सेंटर की स्थापना को मंजूरी। हाथरस, बागपत और कासगंज में मेडिकल कॉलेज च्च्च मोड पर संचालित करने का निर्णय। बलरामपुर में स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना को हरी झंडी। गंगा एक्सप्रेसवे को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ने का ऐतिहासिक फैसला। प्रयागराज–चित्रकूट डेवलेपमेंट रीजन के प्रस्ताव को मंजूरी। यमुना नदी पर नए पुल और प्रयागराज से वाराणसी तक कनेक्टिविटी के लिए फोर लेन ब्रिज का प्रस्ताव पास। युवा सशक्तिकरण योजना के तहत निशुल्क स्मार्टफोन वितरण योजना को मंजूरी। महाकुंभ 2025 को केंद्रित करते हुए विकास और बुनियादी ढांचे के बड़े फैसले।

मेयर ने योगी को स्मृति चिन्ह यमुना जल भेट किया

महाकुम्भ नगर। बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, बृजेश पाठक सहित पूरे मंत्रिमंडल को महापौर उमेश चंद्र गणेश केसरवानी ने महाकुंभ मेला क्षेत्र में कैबिनेट बैठक भोजन के पश्चात यमुना जल से भरा कलश भेंट किया। साथ ही प्रयागराज नगर निगम की ओर से श्संगमश स्मृति चिन्ह भी दिया। इस दौरान महापौर ने मुख्यमंत्री से कहा कि, प्रदेश सरकार ने महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाया है। श्रद्धालुओं के स्नान के लिए पावन गंगा स्वच्छ रूप में बह रही है।

इसका निर्मल प्रवाह बनाए रखने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही हे। अब यमुना जी के जल को भी स्वच्छ बनाया जाए और इसकी शुरुआत दिल्ली से हो। दरअसल, महाकुंभ–2025 के 10वें दिन प्रदेश की योगी सरकार सहित पूरा मंत्रिमंडल प्रयागराज पहुंचा था। यहां कैबिनेट की बैठक हुई और इसके बाद मंत्रीगण ने संगम में स्नान किया। महापौर श्री गणेश केसरवानी ने माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी सहित पूरे मंत्रिमंडल और उच्चाधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने प्रयागराज के विकास और यहां महाकुंभ के दौरान हुए और हो रहे कार्यों के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। साथ ही मुख्यमंत्री जी की ओर से कैबिनेट बैठक में नगर के विकास के लिए आए प्रस्ताव पर मुहर लगने पर खुशी जताई। महापौर ने कहा कि, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन को मुख्यमंत्री लगातार आगे बढ़ा रहे हैं। महाकुंभ के साथ ही प्रयागराज को दिव्य और भव्य बनाया है। आस्था और विश्वास के इस संगम में न केवल श्रद्धालुओं के लिए भक्ति के द्वार खोले, बल्कि सभी को एकता की डोर से बांधा है।

सम्पादक
सिद्धनाथ द्विवेदी
प्रबन्धक निदेशक
दीपक जयसवाल
सम्पादकीय कार्यालय
11ई/2, ताशकंद मार्ग, सिविल लाइन्स, इलाहाबाद

इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पीआरबी एक्ट के अन्तर्गत उत्तरदायी तथा इससे उत्पन्न समस्त विवाद इलाहाबाद न्यायालय के आधीन होगा।

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक सिद्धनाथ द्विवेदी द्वारा काम्पीटेंट बिजनेस सर्विसेज विष्णु पदम कुटीर 115डी/2ई लूकरगंज, इलाहाबाद से मुद्रित एवं 399 कृष्णानगर कीडगंज से प्रकाशित।
सम्पादक–सिद्धनाथ द्विवेदी, आरएनआई नं. UPHIN/2007/22706 रजि.नं. AD-32/2008-09 ईमेलः amritkt.alld@gmail.com फोन नं. : 9453273951, 8799627062